आषाढ़ शुक्ल पक्ष -2-3, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक - 11 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
16 जुलाई 2026 गुरुवार

आज का मौसम
33.6 अधिकतम
25.2 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

दतिया से बांकीपुर तक... टिकटों की राजनीति में छिपे कल के संकेत

उम्मीदवारों से अधिक चर्चा उन नेताओं की है जिन्हें टिकट नहीं मिला। यही बताता है कि असली मुकाबला केवल चुनावी मैदान में नहीं, दलों के भीतर भी चल रहा है।

राजनीति में टिकट केवल चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता, वह पार्टी के मन की बात भी होता है। कई बार जिस नेता को टिकट मिलता है, उससे अधिक चर्चा उस नेता की होती है जिसका टिकट कट जाता है। यही वजह है कि बिहार के बांकीपुर और मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव केवल दो रिक्त सीटों को भरने का चुनाव नहीं रह गए हैं। इन दोनों सीटों ने चार बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने बांकीपुर में आखिरी समय पर उम्मीदवार क्यों बदला? दतिया में डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया? प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी बाज़ी बांकीपुर में ही क्यों लगाई? और कांग्रेस ने अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती के बेटे के बजाय दतिया राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह पर दांव क्यों खेला?

प्रसंगवश

राजेश सिरोठिया

इन सवालों के जवाब ही इन दोनों उपचुनावों का वास्तविक राजनीतिक अर्थ समझाते हैं। बांकीपुर भाजपा का परंपरागत गढ़ माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यहां उम्मीदवार बदलने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन, नामांकन के बाद अभिषेक कुमार सिन्हा के हटने और नीरज कुमार सिन्हा को लाने से यह संदेश जरूर गया कि भाजपा इस सीट पर किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। यह उपचुनाव अब केवल सीट बचाने का चुनाव नहीं, बल्कि भाजपा की संगठनात्मक विश्वसनीयता की परीक्षा भी बन गया है।

इसी सीट को प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया है। वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार स्वयं मतदाताओं के बीच परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने किसी आसान सीट के बजाय बीजेपी के मजबूत गढ़ में चुनौती दी है। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जन सुराज को नई ऊर्जा मिलेगी, और यदि पीछे रह जाते हैं तो यह सवाल भी उठेगा कि चुनावी रणनीतिकार होना और जननेता बनना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस मुकाबले को और रोचक बनाने के लिए राजद ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी लड़ाई केवल भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच नहीं, बल्कि बिहार की भावी राजनीतिक धुरी तय करने की भी है।

अब दतिया की ओर आइए। यहां भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पार्टी ने इसके पीछे कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इतना बड़ा फैसला केवल एक विधानसभा सीट को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाता। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि संगठन किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। दतिया का फैसला उसी सोच का विस्तार माना जा सकता है। नरोत्तम जैसे प्रभावशाली नेता का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। अंततः उन्हें स्वयं आगे आकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना पड़ा। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि बड़े फैसले लेना जितना कठिन होता है, उन्हें संगठन में स्वीकार कराना उससे कहीं अधिक कठिन होता है। कांग्रेस का फैसला भी कम दिलचस्प नहीं है। अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट देने की अटकलें लंबे समय तक चलती रहीं। यदि कांग्रेस चाहती तो सहानुभूति का कार्ड खेल सकती थी। लेकिन उसने घनश्याम सिंह पर दांव लगाकर अलग रास्ता चुना। यह फैसला बताता है कि कांग्रेस केवल भावनात्मक राजनीति के भरोसे नहीं रहना चाहती, बल्कि स्थानीय सामाजिक समीकरणों और व्यापक स्वीकार्यता के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है।

30 जुलाई को मतदाता केवल दो विधायकों का फैसला नहीं करेंगे। वे यह भी तय करेंगे कि राजनीतिक दलों ने टिकटों के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की थी, उसे जनता ने स्वीकार किया या नहीं। राजनीति में कई बार बड़े बदलावों की आहट छोटे उपचुनावों से सुनाई देती है। दतिया और बांकीपुर शायद ऐसी ही एक आहट हैं।

भाजपा की आंतरिक राजनीति की भी परीक्षा

दतिया की जातीय राजनीति में ब्राह्मण और जाटव मतदाताओं के बाद तीसरा सबसे बड़ा सामाजिक समूह कुशवाहा समाज का है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत मानी जाती है। जिले के भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर शरण कुशवाहा नरोत्तम मिश्रा के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने संगठन के फैसले से असहमति जताते हुए इस्तीफा भी दिया था, हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भाजपा ने स्थानीय संगठन पर निर्भर रहने की बजाय ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को प्रभारीऔर प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह प्रभारी बनाया। राहुल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विश्वस्त माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी भूमिका केवल चुनावी प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे मुख्यमंत्री की ओर से पूरे चुनाव अभियान की सीधी निगरानी भी करेंगे। जैन समाज में उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए भाजपा इस वर्ग के मतों के ध्रुवीकरण की भी उम्मीद कर रही है। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा के भीतर चल रहे घटनाक्रम को अपने पक्ष में जाता हुआ बता रहे हैं। उनका दावा है कि भाजपा की अंदरूनी खींचतान का लाभ कांग्रेस को मिलेगा और पार्टी दतिया उपचुनाव लगभग 25 हजार मतों के अंतर से जीतेगी। अंतिम फैसला तो मतदाता ही करेंगे, लेकिन इतना तय है कि दतिया का मुकाबला अब केवल दो दलों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, संगठनात्मक रणनीति और भाजपा की आंतरिक राजनीति की भी परीक्षा बन चुका है।

भक्ति के पहियों पर निकले प्रभु जगन्नाथ
आस्था, उत्साह और परंपरा का महाकुंभ

ओड़िशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू हो गई। तीनों भव्य रथ पूरी तरह सजकर ग्रैंड रोड पर निकल रहे हैं। देश-विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं।

सोने की झाड़ू से रथों की सफाई

09 दिन रथ यात्रा की अवधि।

03 रथ भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के निकलते हैं।

30 लाख भक्तों के पुरी आने की संभावना

19	12000	1700	100	500
आईपीएस रथ यात्रा के लिए पुरी में तैनात।	पुलिसकर्मी भीड़ और व्यवस्था संभाल रहे।	बायो-टॉयलेट की व्यवस्था की गई।	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधन देखेंगे।	सीसीटीवी कैमरे रथ यात्रा के मार्ग पर लगे।

65 एलईडी स्क्रीन श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए लगाई गईं।

88 अस्थायी अस्पताल आपात स्थिति के लिए बनाए गए।

नीट पेपर लीक मामला ... कोर्ट के सामने सीबीआई का बड़ा खुलासा

कोचिंग संचालक ने 5 लाख में खरीदे थे केमिस्ट्री के सवाल, 111 प्रश्न हूबहू मिले

नई दिल्ली, एजेंसी

नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार एक कोचिंग सेंटर संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान किया था। आरोपी को मिले 120 प्रश्नों में से 111 सवाल वास्तविक नीट प्रश्नपत्र से मेल खा गए।

सीबीआई ने यह जानकारी आरोपी कोचिंग संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष अदालत के समक्ष दी। एजेंसी का दावा है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा था, जिसमें प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाई गई थी। जांच के मुताबिक, मोटेगांवकर ने लीक प्रश्न पी.वी. कुलकर्णी से प्राप्त किए थे। कुलकर्णी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के उस विशेषज्ञ पैनल का सदस्य था, जो प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल था। सीबीआई का आरोप है कि कुलकर्णी ने गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के प्रश्न उपलब्ध कराए।

एजेंसी के अनुसार, मोटेगांवकर का बेटा कुलकर्णी के कोचिंग संस्थान केमिस्ट्री ट्यूटोरियल क्लासेस में पढ़ता था। इसी संपर्क का फायदा उठाकर प्रश्न हासिल किए गए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि प्रश्न मिलने के बाद मोटेगांवकर ने अपने हाथ से नोट्स तैयार किए और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर छात्रों को पढ़ाया। ताजा खुलासे ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा की गोपनीयता किस तरह भंग हुई और प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल लोगों तक परीक्षा माफिया की पहुंच कैसे बनी। अब इस मामले में अदालत का फैसला और सीबीआई की आगे की जांच दोनों पर देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजरें टिकी हैं।

नीट-यूजी 2024 का पेपर लीक मामला पिछले वर्ष देश के सबसे चर्चित शिक्षा घोटालों में शामिल रहा। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कई राज्यों से पेपर लीक, प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध होने और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच के दौरान बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने अब तक अनेक चार्जशीट दाखिल की हैं और परीक्षा माफिया, बिचौलियों तथा प्रश्नपत्र तक पहुंच रखने वाले लोगों के नेटवर्क की पड़ताल जारी है।

हाथ से लिखी गई लिस्ट से पेपर का मिलान

जांच में बरामद इन हस्तलिखित नोट्स का मिलान वास्तविक प्रश्नपत्र से किया गया, जिसमें 120 में से 111 प्रश्न हूबहू या बेहद करीब पाए गए। सीबीआई का कहना है कि यह तथ्य अपने आप में इस बात का मजबूत प्रमाण है कि परीक्षा से पहले गोपनीय प्रश्नों तक अवैध पहुंच बनाई गई थी। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, दस्तावेज और अन्य गवाहों के बयान भी उपलब्ध हैं, इसलिए उसे जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

हरदा में 12 घंटे बाद किसानों ने खत्म किया चक्काजाम

हरदा। हरदा में आम किसान यूनियन द्वारा इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह से जारी चक्काजाम देर रात स्थगित कर दिया गया। यह प्रदर्शन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी, खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करने और फसल बीमा की मांगों को लेकर किया गया था। किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से मुलाकात कर अपनी प्रमुख मांगों पर विस्तृत चर्चा की। प्रशासन ने किसानों को उनकी मांगों को कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया।

छात्रसंघ चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जबलपुर, दोपहर मेट्रो। मध्य प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2017 से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर जारी कर उसमें छात्रसंघ गठन और चुनाव प्रावधान स्पष्ट किए जाएं तथा जानकारी न्यायालय को दी जाए। अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2017 से प्रदेश के शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया ठप है। सरकार की ओर से बताया गया कि सत्र 2026-27 का कैलेंडर अंतिम चरण में है।

ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले जारी

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिका ने आज तड़के ईरान में सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर एयरस्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, रक्षा ठिकाने और सिस्तान-बलूचिस्तान में 388वीं ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया।

जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया, जबकि जॉर्डन ने तीन ईरानी मिसाइलें मार गिराने की जानकारी दी।

इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता है तो ईरान बड़े सैन्य टकराव के लिए तैयार है।

आज का कार्टून

मेट्रो एंकर अगले साल चुनाव, इसलिए 'बाबा' को हटाकर सहानुभूति नहीं देना चाहती भाजपा

अपने ही हुए बागी... रीवा महापौर की कुर्सी पर संकट के बादल!

आशीष द्विवेदी, रीवा

रीवा में कांग्रेस के महापौर अजय मिश्रा बाबा लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। हालत यह है कि अब उनकी मेयर इन काउंसिल पर भी संकट है। राजनीतिक गलियारों में सवाल भी उठ रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद महापौर को हटाने का कदम क्यों नहीं उठा रही है। कहा जा रहा है कि चूंकि, एक साल बाद चुनाव है इसलिए पार्टी उन्हें सहानुभूति नहीं देना चाहती।

रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में भाजपा 30 और कांग्रेस के 14 पार्षद हैं। लेकिन, महापौर के लिए बड़ी परेशानी विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस के अधिकांश पार्षद खुलकर उनकी कार्यशैली का विरोध कर चुके हैं। चर्चा है कि 14 में से केवल गिने.चुने पार्षद ही उनके समर्थन में बचे हैं। 10 सदस्यीय मेयर इन काउंसिल में भी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। वार्ड 27 के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य मनीष नामदेव का सोशल मीडिया पर लिखा संदेश 'मत समझो कि खामोशी हमारी हार है, यह तो बस धैर्य का संस्कार है', नगर निगम की राजनीति में बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

अजय मिश्रा, महापौर

वेंकटेश पांडे, अध्यक्ष

कांग्रेस के पार्षदों की बढ़ती नाराजगी

हाल ही में वार्ड 44 में आयोजित एक कार्यक्रम ने महापौर को नए विवाद में ला दिया। आरोप है कि कार्यक्रम में संबंधित वार्ड कि कांग्रेस पार्षद अर्चना मिश्रा को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस पर कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी जताई। वार्ड 11 की पार्षद रश्मि विनोद शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपमान बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई।

महापौर - अध्यक्ष की दोस्ती

नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भाजपा से हैं जबकि महापौर कांग्रेस से। दोनों की पुरानी मित्रता राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी रहती है। हालांकि भाजपा के भीतर अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर भी समय- समय पर असंतोष सामने आता रहा है। पार्टी के कई पार्षद पहले भी विरोध जता चुके हैं जिसे बाद में संगठन स्तर पर शांत कराया गया। बाबजूद इसके अध्यक्ष को भाजपा संदेह की नजर से देखने लगी है। बताया गया है कि पांच माह पहले अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा के पार्षद लामबंद हो गए थे। तब अध्यक्ष को बचाने महापौर ही सामने आए थे और ताल ठोंककर कहा था 'ये मेरी दोस्ती का इम्तिहान है।

विश्वकर्मा नगर के हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर जर्जर, डर के साए में जी रहे लोग

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी के विश्वकर्मा नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर लगातार जर्जर होते जा रहे हैं। कई इमारतों की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, छतों का प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है और सीढ़ियों सहित कई हिस्सों की हालत बेहद खराब हो गई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

स्थानीय रहवासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। छतों से पानी टपकता है, दीवारों में सीलन बढ़ जाती है और भवनों की मजबूती पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद केवल आश्वासन मिले, लेकिन मरम्मत या पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। रहवासियों का आरोप है कि इन जर्जर क्वार्टरों में सैकड़ों परिवार वर्षों से रहने को मजबूर हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर बना रहता है कि कहीं भवन का कोई हिस्सा गिरकर बड़ा हादसा न हो जाए। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि विश्वकर्मा नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का तत्काल तकनीकी सर्वे कराया जाए, जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण कराया जाए तथा जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। बरसात के इस मौसम में यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन रहवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कब तक इस समस्या का समाधान करता है।

भोपाल डबल मर्डर का खुलासा: करोड़ों की संपत्ति के लिए रची थी मौत की साजिश

फर्जी दानपत्र, तीन लाख का कर्ज और 1500 सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल के ऐशबाग स्थित सुदामा नगर में रिटायर्ड दंपती हेमंत फिलेमोन और शकुंतला बारीक की हत्या का राज आखिरकार 20 दिन बाद खुल गया। शुरुआत में पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर माने जा रहे इस मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही शकुंतला बारीक को तीन लाख रुपये उधार देकर मकान का कथित दानपत्र (गिफ्ट डीड) अपने पक्ष में तैयार कराया। बाद में जब दंपती ने मकान बेचने की तैयारी शुरू की तो आरोपियों को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने 24 जून की रात देसी पिस्टलों से दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी। 27 जून को घर से शव मिलने के बाद शुरू हुई जांच में 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया।

दानपत्र था हत्या की साजिश की नींव

शकुंतला बारीक आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं और उन पर बैंक व निजी लोगों का कर्ज था। उन्हें तत्काल पांच लाख रुपये की जरूरत थी, लेकिन प्रॉपर्टी कारोबारी श्रीकांत ने उन्हें तीन लाख रुपये उधार दिए। इसके बदले मार्च 2025 में सुदामा नगर स्थित करीब सवा करोड़ रुपये के मकान का कथित दानपत्र तैयार कराया गया। दस्तावेज में उल्लेख था कि पति हेमंत फिलेमोन की मृत्यु के बाद मकान शकुंतला के नाम होगा और वह इसे श्रीकांत को दान कर देंगी। पुलिस जांच में सामने आया कि हेमंत को इस पूरे दस्तावेज की भनक तक नहीं थी।

मकान की बिक्री ने बदल दिया पूरा खेल

पुलिस जांच के अनुसार दंपती सुदामा नगर स्थित अपने मकान को बेचने की तैयारी कर रहे थे और उसका सौदा लगभग तय हो चुका था। जांच एजेंसी का मानना है कि यदि मकान बिक जाता तो कथित दानपत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता और आरोपियों की पूरी योजना विफल हो जाती। इसी आशंका के चलते संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से दंपती की हत्या की साजिश रची गई। दो देसी पिस्टलों का इंतजाम किया गया और 24 जून की रात घर में घुसकर दोनों को गोली मार दी गई। पुलिस का दावा है कि हत्या का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पर कब्जा करना था।

तकनीकी साक्ष्य और लगातार निगरानी, कैमरे किए ट्रेस

इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में एसआईटी और क्राइम ब्रांच की करीब 20 टीमों ने लगातार जांच की। जांच के दौरान 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन, डिजिटल साक्ष्यों तथा वैज्ञानिक विश्लेषण का सहारा लिया गया। घटना वाली रात आरोपियों की गतिविधियों को कई कैमरों में ट्रेस किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर पुलिस दोनों सगे भाइयों तक पहुंची और पूछताछ के बाद पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया।

अंधविश्वास: खजाने के लालच में पिता ने ही ले ली बेटी की जान

भोपाल। दोपहर मेट्रो

सूखीसेवनिया क्षेत्र में तीन महीने पहले लापता हुई नाबालिग बालिका की गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया। भोपाल देहात पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जमीन में गड़े सोने-चांदी के खजाने को पाने के अंधविश्वास में पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने में उसके दो साथी भी शामिल थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि 3 अप्रैल 2026 को बालिका की मां ने सूखीसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि खलिहान में सोते समय उसकी नाबालिग बेटी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई।

खेत में मानव कंकाल मिला

जांच के दौरान 7 मई को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में मानव कंकाल मिला। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिता ने पहले बेटी की डंडे से पिटाई की, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। नब्ज देखकर मौत की पुष्टि करने के बाद शव को खेत में दफना दिया गया। इसी दौरान पिता के अचानक घर छोड़कर फरार होने और पत्नी द्वारा उसके व्यवहार पर संदेह जताने से पुलिस का शक गहरा गया। साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ।

भोपाल। वार्ड 10 ईदगाह हिल्स में लगभग 1 करोड़ 25 लाख की लागत से विभिन्न (सड़क) विकासकार्यों का भूमिपूजन हुआ। इस अवसर पर सासंद आलोक शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद सरोज हरिओम असेरी, जिला मंत्री राकेश कुकरेजा, मंडल अध्यक्ष यतेन मकवाना, पदाधिकारीगण सिंधी पंचायत कमेटी के सदस्य गण एवं रहवासी उपस्थित रहे।

भोपाल के ISBT पर मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान

असिस्टेंट कमांडेंट की गाड़ी रोकी: 10 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटवाई, 13 वाहनों के बनाए चालान

भोपाल। दोपहर मेट्रो

राजधानी के आईएसबीटी पर जिला न्यायालय के निर्देश पर विशेष मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान चलाया गया। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजीएम) आग्नीध्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में तीन अन्य मजिस्ट्रेट, चार थानों की पुलिस ने यह अभियान चलाया।

इसमें पुलिस टीम ने वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट की गाड़ी रोकी गई। लेकिन दस्तावेज पूरे होने पर उन्हें जाने दिया गया। लगभग 10 वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई और उनपर चालानी कार्रवाई की गई।

एक डंपर को किया जब्त

अभियान के दौरान कुल 13 वाहनों के चालान किए गए। इनमें 10 वाहनों से ब्लैक फिल्म हटवाई गई, जबकि एक वाहन पर सर्च लाइट लगाने और एक वाहन पर नंबर प्लेट नहीं होने के कारण चालान किया गया। इसके अलावा एक डंपर को दस्तावेज होने पर न होने पर जब्त किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह विशेष अभियान चलाए जाएंगे। वाहन चालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

एमआईसी बैठक में अनुदान और पांडाल अनुमति पर छिड़ी बहस

सदस्यों ने फैसलों पर जताई आपत्ति, आयुक्त ने शासन के नियमों का दिया हवाला

भोपाल। दोपहर मेट्रो

नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में अनुदान और गणेश-दुर्गा उत्सव के लिए पांडाल शेड निर्माण की अनुमति का मुद्दा प्रमुखता से उठा। इस दौरान एमआईसी सदस्यों और निगम आयुक्त संस्कृति जैन के बीच तीखी बहस हुई। सदस्यों का कहना था कि जिन समितियों के लिए बजट में अनुदान का प्रावधान पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उनकी फाइलों को रोका जाना उचित नहीं है। वहीं, पांडाल निर्माण की अनुमति पर रोक लगाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई।

एमआईसी सदस्य जितेंद्र शुक्ला और सुषमा बवीसा ने कहा कि यदि किसी स्थान पर अतिक्रमण की आशंका है तो निगम नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन अनुमति देने की प्रक्रिया नहीं रोकी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर आयुक्त के हस्ताक्षर होने के बाद उसके स्वीकृत प्रावधानों पर एकतरफा रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने शासन के निर्देशों और नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही। बहस के दौरान आयुक्त कुछ देर के लिए बैठक से उठीं, लेकिन बाद में फिर बैठक में शामिल हो गईं।

प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

बैठक में 14 इंजीनियरों और दो सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य अधिकारी पद पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदमपुर छावनी में प्रतिदिन आने वाले करीब 850 टन ठोस कचरे के निष्पादन के लिए 34.82 करोड़ रुपये से अधिक का टेंडर भी स्वीकार किया गया। वहीं, 400 टीपीडी क्षमता वाले बायो-सीएनजी प्लांट का कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण संबंधित संस्था का अनुबंध निरस्त कर नई निविदाएं बुलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अरेड़ी आवासीय परियोजना में 56 नॉन-स्लम ईडब्ल्यूएस आवासों के आवंटन के लिए पहले से तय चयन प्रक्रिया को यथावत रखने पर भी सहमति बनी।

हज यात्रा 2027 के लिए आवेदन शुरू

भोपाल। हज-2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मप्र राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रदेश के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।

मेट्रो एंकर

पूर्वी मध्यप्रदेश में सूखे जैसे हालात, 19 जुलाई से फिर तेज बारिश की उम्मीद

एमपी में थमा मानसून, 35 जिलों में बारिश बेहद कम

भोपाल। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पिछले एक सप्ताह से थमी हुई है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। लगातार सात दिनों से कहीं भी भारी या अति भारी बारिश नहीं होने का असर सबसे ज्यादा पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग समेत 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 11 प्रतिशत कम है। पूर्वी हिस्से में वर्षा की कमी 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।

पूर्वी एमपी में सबसे ज्यादा चिंता

बारिश की सबसे ज्यादा कमी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिलों में दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में सामान्य से 24 प्रतिशत कम वर्षा होने से कृषि कार्य प्रभावित होने लगे हैं और जल स्रोतों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों की बुवाई और उनकी बढ़वार पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र विकसित हो रहा है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है। इन तीनों सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है।

जुलाई में होती है मानसून की सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की सामान्य वार्षिक वर्षा 37.3 इंच है। जुलाई का महीना मानसून के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है क्योंकि इसी महीने पूरे सीजन की लगभग 40 प्रतिशत बारिश होती है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में सामान्य वर्षा 38 से 39 इंच के बीच रहती है, जबकि जबलपुर में सबसे अधिक 17 इंच से ज्यादा बारिश केवल जुलाई में दर्ज होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश होती है तो प्रदेश में वर्षा का मौजूदा घाटा काफी हद तक कम हो सकता है।

डीजीपी बनकर दी गिरफ्तारी की धमकी 34 हजार ठगे

भोपाल। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने खुद को बिहार पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी बताकर एक युवक को डिजिटल ठगी का शिकार बना लिया। आरोपी ने कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय दिखाते हुए समझौते के नाम पर उससे 34,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित आनंद कुमार के मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बिहार पुलिस का डीजीपी बताया। उसने कहा कि आनंद के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अश्लील वीडियो देखने में हुआ है और इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज होने वाला है। आरोपी ने गिरफ्तारी और बदनामी से बचाने का झांसा देते हुए समझौते के लिए पैसे जमा करा लिए।

श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर

100 करोड़ की लागत से आकार ले रहा आस्था का भव्य धाम

मंत्री सारंग ने किया मंदिर का निरीक्षण

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राजधानी भोपाल के छोला स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नगर निगम एवं संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए परियोजना को तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कॉरिडोर निर्माण का मूल उद्देश्य श्रद्धालुओं को अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने गर्भगृह की मूल संरचना और धार्मिक स्वरूप को पूरी तरह यथावत रखते हुए मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र का विस्तार किया जाए, जिससे मंदिर की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पहचान सुरक्षित रहे।

दर्शनार्थियों की सुविधा पर विशेष जोर

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान श्रद्धालुओं, स्थानीय रहवासियों एवं व्यापारियों को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों के क्रियान्वयन में न्यूनतम विस्थापन सुनिश्चित किया जाए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते की जाएं।

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मिली अंतरराष्ट्रीय उड़ान

सीएम बोले- यह नई सेवा हमारे संकल्प की करेगी पूर्ति मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

भोपाल/इंदौर, दोपहर मेट्रो

एयर ट्रैवलर्स को बड़ी सौगात मिली है। इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर इस नई इंटरनेशनल फ्लाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने फ्लाइट को फ्लैग ऑफ कर इंदौर एयरपोर्ट से रवाना किया। यह इंटरनेशनल मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर सीएम डॉ. यादव ने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से मां अहिल्या की नगरी इंदौर में अंतरराष्ट्रीय उड़ान का ये अवसर अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर राज्य औद्योगिक-आर्थिक प्रगति कर रहा है। इस प्रगति में विमान सेवा महत्वपूर्ण है। आज शुरू होने जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू की जा रही है। यह नई सेवा हमारे संकल्प की पूर्ति भी करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह मुझे अंदर से खुशी दे रहा है। आर्थिक राजधानी इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने से और महत्वपूर्ण हो जाएगी। हमारी विमानन नीति के तहत राज्य के अंदर विमान सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि रीवा-दिल्ली फ्लाइट, रीवा-इंदौर फ्लाइट, रीवा-रायपुर फ्लाइट बेहतर ढंग से संचालित की जा रही हैं। भविष्य में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ-साथ राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन पर भी ध्यान दे रही है। इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर-इंदौर के लिए हेली सर्विस उपलब्ध है।

हर फ्लाइट पर 15 लाख की सब्सिडी देगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। हमारी सरकार बनने के बाद हम इसी भाव पर चल रहे हैं। इंदौर से अबू धाबी जाने के लिए पहले दिल्ली-मुंबई जाना पड़ता है, फिर 7 से 8 घंटे में वहां पहुंचते हैं। लेकिन इंदौर से सीधी उड़ान यात्रियों को महज 3 से 4 घंटे में अबू धाबी पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश विमानन नीति के तहत हर फ्लाइट पर 15 लाख रुपये सब्सिडी देने को तैयार है। इसी के तहत आज यह बड़ी सौगात मिल रही है। इस फ्लाइट का किराया 25 हजार की जगह 12-14 हजार रुपये होगा। इस टिकट में होने वाले भाव का अंतर सरकार वहन करेगी।

आर्थिक मजबूती के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद राज्य में तीन एयरपोर्ट लोकार्पित हुए। इसके अलावा दो एयरपोर्ट उज्जैन और शिवपुरी निर्माणाधीन हैं। इस तरह दस एयरपोर्ट राज्य में उपलब्ध होंगे। हर 75 किमी पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप होगी। हर 45 किमी पर एक हेलीपेड होगा। 230 विधानसभाओं में बनने जा रहे ये हेलीपेड उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत शहडोल-नीमच-छिंदवाड़ा-मंडला इनको भी आरसीएस योजना का लाभ देंगे। खासकर, बीमारों के लिए पीएमश्री एंबुलेंस सेवा जरूरी है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ये सुविधा चालू की। हमारी इस योजना को कई लोग कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अबू धाबी से हमारा गौरवशाली अतीत का संबंध है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए इस प्रकार की फ्लाइट की जरूरत भी है। मैं इस फ्लाइट से जाने वाले लोगों को बधाई देता हूं।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पहली बार बोले

जिन्हें गली में भौं-भौं करने वाला भी नहीं पूछता वह उठा रहे शहर काजी पर सवाल

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने शहर काजी और शहर मुफ्ती के स्वागत को लेकर उठे विवाद पर पहली बार सार्वजनिक मंच से चुप्पी तोड़ी। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आलोचकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जिन्हें गली में भौं-भौं करने वाला भी नहीं पूछता, वही सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि काजी साहब और मुफ्ती साहब मेरे पास क्यों गए।

पटेल ने कहा कि वह स्वयं शहर काजी और शहर मुफ्ती के पास गए थे और सम्मानपूर्वक उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। उन्होंने दावा किया कि दोनों धार्मिक नेताओं ने कार्यक्रम में आकर वक्फ बोर्ड के कामों की सराहना की, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और वक्फ संपत्तियों की ईमानदारी से हिफाजत करने की नसीहत भी दी।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि समाज के बड़े लोगों का सम्मान करना उनके संस्कारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा जब आप अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो बदले में मोहब्बत मिलती है। हमने उन्हें बुलाया, इसलिए वे आए। इसमें गलत क्या है? उन्होंने विरोध करने वालों से कहा कि यदि वे भी अपने सार्वजनिक कार्यों में शहर काजी और शहर मुफ्ती को बुलाएंगे तो उन्हें भी ईमानदारी से काम करने की सीख मिलेगी।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से कुछ लोगों को तकलीफ

सनव्वर पटेल ने दावा किया कि पिछले तीन-चार वर्षों में वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अनियमितताओं पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ संपत्तियों से लगभग कोई आय नहीं होती थी, लेकिन बोर्ड ने कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की वसूली की। उनके अनुसार भोपाल में 29 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई और कई स्थानों पर कब्जे हटाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के हित प्रभावित हुए हैं, वही अब नए बोर्ड और कानून को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि राज्य स्तर के वक्फ बोर्ड और मस्जिदों की प्रबंधन समितियों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नया कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि मस्जिद, मदरसा, दरगाह और स्थानीय वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन समितियों में मुस्लिम सदस्य ही रहेंगे। उनके मुताबिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को केवल राज्य स्तर पर विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है, ताकि प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिल सके।

अब कॉलोनियों में खुल सकेंगे अस्पताल, होटल और उद्योग

बड़ा कदम : मिक्स्ड लैंड यूज नियमों में बदलाव करने की तैयारी में सरकार

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत अब केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है, उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी।

इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्त्रां के साथ-साथ प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे उद्योगों को भी स्थापित किया जा सकेगा।

शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर जताई चिंता

यह बदलाव केवल नए विकसित होने वाले क्षेत्रों (ग्रीन फील्ड एरिया) पर ही प्रभावी होगा और पहले से बसे हुए इलाकों या पुरानी कॉलोनियों के स्वीकृत लेआउट में कोई फेरबदल नहीं करेगा। हालांकि, शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, मप्र के सचिव सुमित गोठी ने चेतावनी दी है कि बिना किसी स्पष्ट और कड़े मानकों के आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने से शहरी अव्यवस्था बढ़ेगी, कॉलोनियों की शांति भंग होगी और नियोजित विकास पर बुरा असर पड़ेगा।

हजारों तक पहुंच सकता है अटैचमेंट शिक्षकों का आंकड़ा

213 शिक्षकों की लिस्ट सामने आने के बाद बढ़ेगी कार्रवाई, सीपीआई के निर्णय में रोड़ा बने कलेक्टर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में स्कूलों से बाहर मंत्रालय, कलेक्टर कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के यहां वर्षों से अटैच होकर काम कर रहे शिक्षकों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मंत्रालय में बाबूगिरी करने और विधायकों के पीए बनकर काम करने वाले 213 शिक्षकों की सूची सामने आने के बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय अब प्रदेशभर से ऐसे शिक्षकों का पूरा ब्योरा जुटा रहा है। विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि यह संख्या सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों तक पहुंच सकती है। इस बीच यह भी सामने आया है कि कई जिलों में कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म करने में रोड़ा बन रहे हैं। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने एक सप्ताह पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए थे कि स्कूलों से बाहर गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगे सभी शिक्षकों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त कर उन्हें मूल पदस्थापना वाले विद्यालय में भेजा जाए। इसके बाद रीवा, जबलपुर, भोपाल समेत कई संभागों में ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें स्कूल लौटने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश जारी होने के बाद लंबे समय से गैर-शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षक अब अपने अटैचमेंट बचाने की कोशिश में जुट गए हैं।

कलेक्टरों पर आरोप

विभागीय सूत्रों के अनुसार कई जिलों में कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यहां तक कि एक आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर एक जिला शिक्षा अधिकारी को अटैचमेंट समाप्त करने की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी तक दे दी। वहीं एक महिला नगर निगम आयुक्त द्वारा भी अटैचमेंट समाप्त करने संबंधी पत्र जारी करने पर जिला शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि संबंधित अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

सभी विभागों में 20 जुलाई तक पदोन्नति की तैयारी

लाखों सरकारी कर्मचारियों का खत्म होने वाला है इंतजार

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा है। सभी विभागों से कहा गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी करके पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएं। दरअसल, सरकार चाहती है कि हाई कोर्ट में पदोन्नति नियम 2025 को लेकर कोई भी निर्णय आने से पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। विभागों में पदोन्नति को लेकर बैठकें लगातार चल रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से एक जुलाई से अब तक की गईं पदोन्नतियों की रिपोर्ट मांगी हैं। उधर, विधानसभा सचिवालय में प्रथम श्रेणी के 15, द्वितीय श्रेणी के 40, तृतीय श्रेणी के 93 एवं चतुर्थ श्रेणी के 34 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया।

लगभग 10 वर्ष बाद पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की गई है

पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार जताते हुए उनका सम्मान किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2002 को हाईकोर्ट द्वारा रद किए जाने के लगभग 10 वर्ष बाद पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस दौरान लगभग एक लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

मेट्रो एंकर | प्रदेश में बिजली संकट का एआई से समाधान निकालने की कोशिश

24 घंटे होगी ग्रिड की स्मार्ट निगरानी, थमेगी अघोषित कटौती

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश में तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग के बीच बिजली कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से ग्रिड संचालन को स्मार्ट बनाने की तैयारी में हैं। इस तकनीक के जरिए बिजली की मांग का पहले से अनुमान लगाया जाएगा। इससे समय पर ग्रिड का बेहतर प्रबंधन और तकनीकी खराबियों की समय रहते पहचान संभव होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना और अघोषित कटौती की स्थिति को कम करना है।

प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकतम बिजली मांग 14,089 मेगावाट थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 18,913 मेगावाट तक पहुंच गई। वर्तमान में यह आंकड़ा करीब 20 हजार मेगावाट के आसपास है। ऊर्जा क्षेत्र के अनुमान के अनुसार वर्ष 2027-28 तक अधिकतम मांग 22 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है। बढ़ती जरूरत को देखते हुए बिजली कंपनियां पारंपरिक व्यवस्था के बजाय डिजिटल तकनीकों पर फोकस कर रही हैं।

एआई से लैस एससीएडीए प्रणाली नियंत्रण केंद्रों को ग्रिड की वास्तविक स्थिति का लगातार आकलन करने में मदद करेगी। इसके जरिए वोल्टेज नियंत्रण, मांग-आपूर्ति संतुलन, आर्थिक डिस्पैच और पीक लोड प्रबंधन जैसे निर्णय अधिक तेजी और सटीकता से लिए जा सकेंगे। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा भी ड्रोन आधारित निरीक्षण व्यवस्था को और उन्नत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एआई आधारित इमेज एनालिसिस तकनीक की मदद से ट्रांसमिशन लाइनों, टावरों और उपकरणों में संभावित खराबियों की समय रहते पहचान की जा सकेगी। इससे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक ट्रिपिंग की घटनाओं में कमी आएगी।

हरित ऊर्जा के लिए भी उपयोगी होगी यह आधुनिक तकनीक

प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। इन स्रोतों का उत्पादन मौसम पर निर्भर होने के कारण इनमें उतार-चढ़ाव बना रहता है। एआई आधारित विश्लेषण प्रणाली मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का बेहतर पूर्वानुमान तैयार कर सकेगी, जिससे ग्रिड संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

एआई से होंगे ये फायदे

- मांग बढ़ने का पहले से मिलेगा अनुमान
- ग्रिड की 24 घंटे स्मार्ट निगरानी
- ड्रोन से ट्रांसमिशन लाइनों की जांच
- खराबी आने से पहले होगी मरम्मत
- ट्रिपिंग और तकनीकी फाल्ट में आएगी कमी
- सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर प्रबंधन

रोजगारधानी

12,099 किमी के नए ग्लोबल इकॉनामिक हब के साथ तैयार हुआ प्रदेश के विकास का खाका

आर्थिक विकास का महाकुंभ... भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन

6 जिलों की 30 तहसीलें, 22 नगरीय निकाय और 2,510 गांवों को अब एक क्षेत्र मानकर विकास

प्रशासनिक केंद्र के साथ अब भोपाल बनने जा रहा है एजुकेशन, फाइनेंस और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हब

वर्ष 2047 में विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में मध्यप्रदेश बनेगा बड़ा भागीदार

स्पेशल डेस्क | भोपाल

मध्यप्रदेश के विकास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी व इसके आसपास के 12,099 वर्ग किमी के क्षेत्र को डॉ. मोहन यादव सरकार ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन (बीएमआर) के तौर अधिसूचित कर दिया है। इस पूरे इलाके को अब एक क्षेत्र मान वन रीजन, वन पॉलिसी के विजन के साथ विकसित किया जाएगा। इसमें भोपाल समेत 6 जिलों के 2,510 गांवों और 30 तहसीलों को शामिल किया गया है। बीएमआर प्रदेश का नया ग्रोथ इंजन होगा, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र भोपाल अपनी शहरी आबादी, विकास की क्षमताओं और नए प्रस्तावित ढांचों के साथ बीएमआर में मुख्य भूमिका अदा करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन के अनुसार, भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन सिर्फ मध्यप्रदेश के विकास के पहिए को रफ्तार ही नहीं देगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 में विकसित भारत के संकल्प में हमारी मजबूत भागीदारी का आधार भी साबित होगा। भोपाल के साथ ही अब बीएमआर के जरिए **रोजगारधानी** के रूप में भी स्थापित होगा।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की झलक बीएमआर की प्लानिंग में भी साफ दिखाई देती है। इस पूरे क्षेत्र की योजना तैयार करते वक्त कई अर्बन प्लानर(शहरी योजनाकारों) को इसमें शामिल किया गया। उनके शोध के आधार यह तय किया गया कि बीएमआर में 'रिएक्टिव प्लानिंग' (समस्या आने पर समाधान) के पुराने ढर्रे को त्यागकर प्रोएक्टिव विजन (भविष्य का पूर्वानुमान) अपनाया जाए। यानी यहां भविष्य के लिए डाटा आधारित पूर्वानुमान के आधार पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।

बीएमआर में शहरों के साथ गांवों के विकास की रफ्तार का भी खासा ख्याल रखा गया है। औद्योगिक विकास के लिए यहां सिंगल विंडो सिस्टम के साथ निवेशकों की हर सहूलियत का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

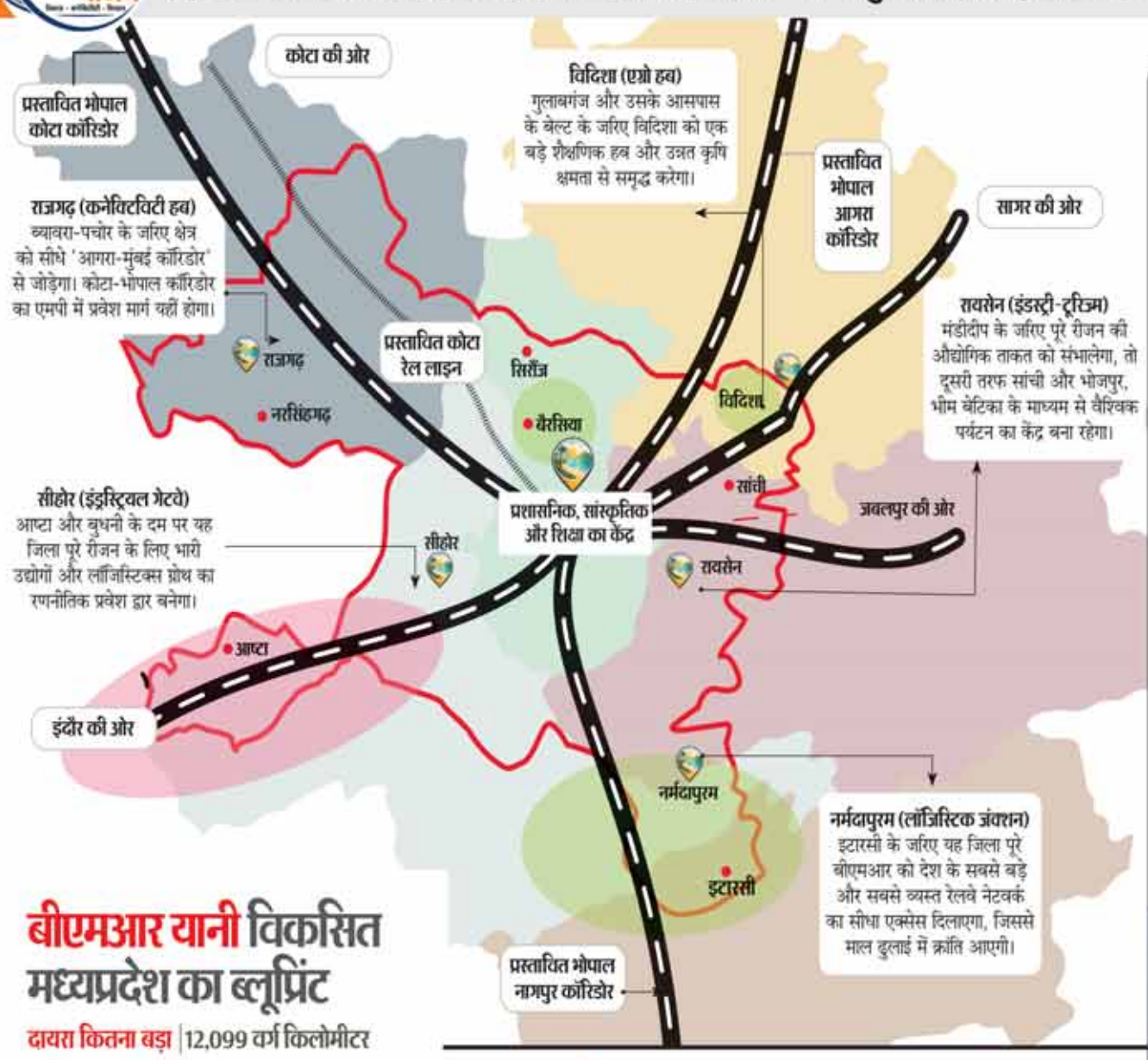

बीएमआर यानी विकसित मध्यप्रदेश का ब्लूप्रिंट

दायरा कितना बड़ा | 12,099 वर्ग किलोमीटर

आर्थिक लक्ष्य | बीएमआर के जरिए विदेशी निवेश लाना और मध्य प्रदेश के सालाना एक्सपोर्ट (निर्यात) को 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचाना।

प्रशासनिक सीमाओं का अंत | डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या कॉपोरेट्स आदि को मंजूरी के लिए अलग-अलग दफ्तरों में नहीं जाना होगा। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वह ताकत होगी कि पूरे क्षेत्र के लिए एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और नियम व मास्टर प्लान तय कर सके।

मकसद क्या है

शहरों की आबादी बढ़ने के बाद आनन-फानन में सड़कें बनाने (रिएक्टिव) के बजाय, अगले 50 साल की जरूरतों को भांपकर पहले से हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रोएक्टिव प्लानिंग) तैयार करना।

महानगरों के बीच गांवों के विकास पर भी फोकस

अक्सर महानगरों के विकास में गांवों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन बीएमआर का मॉडल अलग है। बीएमआर में गांवों की प्राकृतिक संपदा और कृषि भूमि को कंक्रीट के जंगल में नहीं बदला जाएगा। इसके बजाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत हाई-वे, कोल्ड स्टोरेज और सीधे शहरी बाजारों से जोड़ा जाएगा। महानगर की चकाचौंध के बीच गांवों की समृद्धि भी सुनिश्चित होगी।

विकास के संकल्प के मुख्य...4 चरण

सर्वेक्षण-डिजिटल मैपिंग
बीएमआर के 12,099 वर्ग किमी क्षेत्र की सैटेलाइट मैपिंग की जाएगी। इससे मौजूदा संसाधनों और भविष्य की संभावनाओं का डेटाबेस तैयार होगा।

डेवलपमेंट प्लान
डेटाबेस और विभिन्न रिसर्च पेपर्स व अर्बन प्लानिंग गाइडलाइन्स के आधार पर पूरे क्षेत्र का एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। सारी मंजूरियां और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसी आधार पर तैयार होंगे।

फेज-वार विकास
पूरे क्षेत्र को अलग-अलग ग्रोथ फेज में बांटा जाएगा। पहले चरण में कनेक्टिविटी और ऊर्जा नेटवर्क पर काम होगा, जबकि दूसरे चरण में आवासीय और औद्योगिक क्लस्टर्स को विकसित किया जाएगा।

पीपीपी मॉडल
अथॉरिटी का क्रियान्वयन मॉडल निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है कि सरकार के साथ-साथ निजी कंपनियां भी सड़कों, लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश और निर्माण कर सकेंगी।

बीएमआर के 7 प्रमुख स्तंभ

अर्थव्यवस्था
मध्य प्रदेश को 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनामी बनाने का ग्रोथ इंजन।

हेल्थकेयर
पूरे क्षेत्र में 2200 से अधिक हेल्थ यूनिट्स का समान वितरण।

लॉजिस्टिक सपोर्ट
इटारसी के पास बड़े लॉजिस्टिक हब बनेंगे, माल ढुलाई तेज-सस्ती होगी।

पर्यावरण | जल क्षेत्र सुरक्षित; वन, तालाबों झीलों के ईको-सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं।

पर्यटन
77 लाख पर्यटकों के लिए सांची, भीमबेटका और भोजपुर को जोड़ता 'टूरिज्म सर्किट।

मेट्रो का विस्तार
भविष्य में मेट्रो रेल को भोपाल की सीमाओं से बाहर निकालकर औद्योगिक क्षेत्रों तक ले जाने की योजना है।

40 फीसदी बचेगा समय
नेशनल और स्टेट हाईवे का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि रीजन के किसी भी कोने से मुख्य शहर पहुंचने में समय 40% कम लगेगा।।

सुविधाएं: अब एकीकृत व्यवस्था से बढ़ेगी प्रदेश की इकॉनमी

2.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार 'सिंगल विंडो' मॉडल

भोपाल

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन मध्यप्रदेश के 2.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम है। रीजन के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके साथ ही कच्चे माल की व्यवस्था, माल की सुगम आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का एकीकृत ढांचा तैयार होगा। एकीकृत क्षेत्र होने से व्यापार करने की लागत में 15 से 20% की कमी आएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि बीएमआर का गठन सिर्फ जमीन के रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक क्रांति के लिए किया गया है।

कैसे बदलेगी अर्थव्यवस्था?

इंडस्ट्रियल क्लस्टर
विदिशा से लेकर सीहोर तक फैले औद्योगिक क्षेत्रों को एक ही ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

लॉजिस्टिक हब
इटारसी और भोपाल के बीच रेल और सड़क मार्ग का ऐसा जाल होगा कि माल की आवाजाही 40% तेजी से होगी।

बड़े बाजारों से अब सीधे जुड़ेंगे किसान
- नरसिंहगढ़, आष्टा व सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा फूड पार्क और कोल्ड स्टोरेज चेन से जोड़ा जाएगा। किसान का माल खेत से सीधे विदेशी बाजार के लिए पैक होगा।
- गांवों के किसानों को सीधे मंडियों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से जोड़ा जाएगा।

वन रीजन-वन विजन

6 जिले, 30 तहसीलें और 2,510 गांव; जानिए आपकी हिस्सेदारी

बीएमआर का भौगोलिक ढांचा इतना विशाल है कि इसमें कई छोटे देशों जितनी जमीन समाहित है। गजट नोटिफिकेशन और 'एरिया स्टेटमेंट' के बारीक विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार ने विकास को सिर्फ भोपाल शहर तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसका जाल दूर-दराज के गांवों तक फैलाया है। ***जानें किस जिले का कितना हिस्सा बना मेट्रोपॉलिटन रीजन का हिस्सा...***

82.25% | भोपाल
हुजूर और कोलार तहसीलें पूरी तरह (100%) बीएमआर में हैं। बैरसिया का भी 65.54% हिस्सा इसमें शामिल है।

11.00% | विदिशा
विदिशा नगर और आसपास के तकरीबन 408 गांव विकास के इस महाभियान का हिस्सा हैं।

84.00% | रायसेन
सांची (84%) और गौहरगंज (91%) तहसीलों का बड़ा हिस्सा शामिल होने से यह जिला बीएमआर का सांस्कृतिक हृदय बनेगा।

46.00% | राजगढ़
नरसिंहगढ़ तहसील 100% रूप से बीएमआर का हिस्सा बन गई है, जो इसे एक नए औद्योगिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका देगा।

50.00% | सीहोर
सीहोर और श्यामपुर जैसी तहसीलों का बड़ा हिस्सा अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग का हिस्सा होगा। आष्टा का 65% हिस्सा भी इसमें जोड़ा गया है।

07.00% | नर्मदापुरम
इटारसी और सिवनी मालवा के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जोड़ा गया है।

जानिए कैसे होंगे काम... पूरे क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान, हर काम के लिए बीएमआरडीए ही सुप्रीम अथॉरिटी

विकास के पैमाने पर अब सीमाओं की बाधाएं होंगी खत्म

भोपाल/इंदौर

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन को वर्ष 2025 के मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसके तहत सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीएमआरडीए) का गठन किया जा रहा है।

यह अथॉरिटी ही पूरे 12,099 वर्ग किलोमीटर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के साथ सभी मंजूरियों से जुड़े काम करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रशासनिक सीमाओं के फेर में सालों-साल अटकने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स अब एक ही झटके में क्लीयर होंगे। सरकार द्वारा तैयार किए गए अथॉरिटी के नए ड्राफ्ट नियमों के लागू होते ही भोपाल सहित सभी 6 जिलों के विकास में नगर निगमों, पंचायतों और जिला प्रशासनों की सरहदें कभी रोड़ा नहीं बन पाएंगी।

वन रीजन-वन पॉलिसी... आसान भाषा में समझिए, आपके फायदे की हर बात

एक क्षेत्र मानकर होगा विकास
प्रशासनिक सरहदों का रोड़ा हमेशा के लिए खत्म होगा। पहले अगर कोई सड़क भोपाल की सीमा से निकलकर रायसेन या सीहोर जिले में जाती थी, तो दोनों जिलों के अलग-अलग मास्टर प्लान और तालमेल की कमी के कारण प्रोजेक्ट सालों लटके रहते थे।

उद्योगों के लिए रेड कारपेट
उद्योगों और निवेश के लिए रेड कारपेट के साथ स्वागत होगा। पूरे 6 जिलों के रीजन में एक समान व्यवस्था से व्यापारियों को बिजनेस करने में आसानी होगी। कंपनियों को अलग-अलग जिलों के नियमों-मंजूरियों से नहीं जूझना होगा, जिससे पूरे रीजन में निवेश बढ़ेगा।

ताकत क्या होगी
सीहोर की सड़क से लेकर राजगढ़ के इंडस्ट्रियल पार्क और विदिशा के सीवेज सिस्टम तक हर बड़ी योजना की डिजाइन, फंडिंग और एक्जीक्यूशन यही अथॉरिटी तय करेगी।

पहले सुविधाएं, फिर शुल्क : नए ड्राफ्ट नियमों के तहत जब अथॉरिटी किसी क्षेत्र में पूरी तरह सुविधाएं विकसित कर लेगी, तभी उसका एक यूजर तय किया जाएगा। यानी पहले सर्विस मिलेगी, फिर शुल्क।

ईज ऑफ लिविंग
मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने का एक बड़ा फायदा 'अफोर्डेबल हाउसिंग' (किफायती आवास) के रूप में सामने आएगा। भोपाल जैसे मुख्य शहरों के बजाय पास के उपग्रह कस्बों में भूमि की उपलब्धता अधिक और सस्ती होगी।

सार्वजनिक सेवाओं में सुधार
इंटीग्रेटेड जलापूर्ति, आधुनिक स्वच्छता प्रणाली और डिजिटल अधोसंरचना के जरिए नागरिक सेवाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा। पूरे रीजन के लिए एक समन्वित नियंत्रण प्रणाली करेगी, इससे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का रिस्पांस टाइम भी कम होगा।

D-11061/26

अर्बन-रूरल सिनर्जी

2,510 गांवों की खेती से चमकेगा बीएमआर; सीहोर का शरबती रायसेन का बासमती बनेगा मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की ताक़त

स्पेशल रिपोर्ट | भोपाल

अक्सर महानगरों के विकास में गांवों की उपजाऊ जमीनें और खेती खत्म हो जाती है, लेकिन भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन (बीएमआर) देश का पहला ऐसा मास्टरप्लान है जो पूरी तरह 'अर्बन-रूरल सिनर्जी' पर काम करेगा। इसका सीधा अर्थ है कि शहरी और ग्रामीण विकास एक-दूसरे की ताकत बनेंगे।

लगभग 12,099 वर्ग किमी में फैले इस रीजन के 2,510 गांव विकास की इस दौड़ में पीछे नहीं छूटेंगे, बल्कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे क्षेत्रीय वैल्यू चेन से जोड़ा जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में प्राइमरी सेक्टर (कृषि और इससे जुड़ा क्षेत्र) 8.1% की शानदार वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यह राज्य के औसत (7.3%) और राष्ट्रीय औसत (4.4%) से काफी ज्यादा है।

बदलाव... राजगढ़-श्यामपुर में बनेंगे एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, पशुपालन और मत्स्य पालन से खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार

ओडीओपी के साथ ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेंगे हमारे उत्पाद

उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना को मास्टरप्लान से जोड़ा गया है। सीहोर का मशहूर 'शरबती गेहूं' और रायसेन का 'बासमती चावल' इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा।

एग्रो-प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हब

किसानों की फसल खेत से सीधे विदेशी बाजार तक पहुंच सके और उन्हें बेहतर दाम मिलें, इसके लिए राजगढ़ और श्यामपुर क्लस्टर को 'एग्रो-प्रोसेसिंग' (खाद्य प्रसंस्करण) और पैकेजिंग के बड़े हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

कृषि उपकरणों का निर्माण

उन्नत खेती के लिए विदिशा जिले को 'एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट' (कृषि उपकरण) मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ती और आधुनिक मशीनरी मिलेगी।

पशुपालन और मत्स्य पालन में उछाल

बीएमआर की ग्रामीण इकॉनामी केवल फसलों तक सीमित नहीं है। प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट में पशुपालन का 16.1% और मत्स्य पालन व एक्वाकल्चर का 1.2% का मजबूत योगदान है। भोपाल, सीहोर और राजगढ़ पशुपालन के बड़े केंद्र बनकर उभर रहे हैं, जबकि भोपाल मछली पालन में अग्रणी है।

मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ शहरी बाजारों से सीधा जुड़ाव

बीएमआर के ग्रामीण इलाकों में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42% है। यह शहरी क्षेत्रों के मुकाबले 8% अधिक है, जो इस क्षेत्र में कृषि की मजबूती को दर्शाता है। रीजन में कुल 7.71 लाख से अधिक श्रमिक (करीब 41.4%) प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हैं, जिनमें राजगढ़ (74.8%) और सीहोर (69.7%) की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अब इन किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को महानगर के हाईटेक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे गांव का माल सीधे शहर के बड़े बाजारों, मॉल्स, कोल्ड स्टोरेज और एक्सपोर्ट यूनिट्स तक पहुंचेगा। यह 'अर्बन-रूरल सिनर्जी' सुनिश्चित करेगी कि शहर के विकास के साथ-साथ गांवों में भी शहर जैसी समृद्धि और आधुनिक सुविधाएं पहुंचें।

विकास भी-विरासत भी.. मध्यप्रदेश की संस्कृति को मिलेगा नया मंच

पर्यटन के नए ग्लोबल मॉडल के साथ पूरी दुनिया को लुभाएगा देश का दिल

दो विश्व धरोहर स्थलों के साथ मां नर्मदा की आस्था से पर्यटन मानचित्र पर मजबूत दस्तक

भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नव-गठित भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन केवल औद्योगिक और तकनीकी विकास का ही केंद्र नहीं बनने जा रहा, बल्कि यह 'विकास भी-विरासत भी' के मूल मंत्र को जमीन पर उतारते हुए देश का सबसे बड़ा ग्लोबल टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। 12,099 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रीजन में प्राचीन इतिहास, आध्यात्मिक चेतना, प्राकृतिक सौंदर्य और मां नर्मदा की आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखता है।

बीएमआर की सबसे बड़ी ताकत इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। इस पूरे क्षेत्र के केंद्र में दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं-सांची और भीमबेटका। ये दोनों साइट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक अलग सांस्कृतिक प्रतिष्ठा दिलाती हैं बीएमआर के पर्यटन ढांचे में भोजपुर-भीमबेटका कॉरिडोर सबसे बड़ा क्राउड-पुलिंग (पर्यटकों को खींचने वाला) केंद्र है। अपनी गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक अपील के कारण, अकेले भोजपुर ने साल 2024 में 3.59 मिलियन (35.9 लाख) श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित किया, जो इसे क्षेत्र का सबसे पसंदीदा स्थल बनाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस रीजन में हब एंड स्पोक मॉडल की तर्ज पर विकास किया जाएगा। भोपाल शहर एक मुख्य 'हब' (केंद्र) के रूप में काम करेगा। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के जरिए स्पोक्स (जैसे- सांची, भीमबेटका, भोजपुर) तक ले जाया जाएगा।

धर्म-संस्कृति और आध्यात्म के साथ प्रकृति की जुगलबंदी

हाईस्पीड कनेक्टिविटी और पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ अब दुनिया को लुभाएगी हमारी विरासत

पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए 'इको-टूरिज्म' का विस्तार

सरकार हरित संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना उनका संवर्धन कर रही है। बीएमआर का 18.8% हिस्सा (2,285 वर्ग किमी) घने वनों से आच्छादित है, जिसमें रातापानी और चिड़ी-खो जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सफारी जैसे कई इनोवेटिव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए सीहोर और विदिशा में 7 विशेष इको-टूरिज्म गांवों को विकसित किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर पाटने के लिए पर्यटन नीति 2025

हालांकि, आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी साफ हुआ है कि जहां भोपाल, सांची और विदिशा के मुख्य क्षेत्रों में बेहतरीन होटल और कनेक्टिविटी नेटवर्क उपलब्ध हैं, वहीं सीहोर के ग्रामीण बेल्ट और रायसेन के आंतरिक हिस्सों में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होना बाकी है। इस खाई को पाटने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन नीति, 2025 के तहत निजी निवेश को बड़े स्तर पर आमंत्रित किया जा रहा है। नीति के तहत नए प्रोजेक्ट्स के लिए 15% की कैपिटल सब्सिडी और पुरानी हेरिटेज इमारतों को री-डेवलप करने के लिए 90 वर्ष की दीर्घकालिक लीज दी जा रही है।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा पर्यटकों का आंकड़ा

वर्ष	पर्यटक
2011	19.4 लाख
2024	77.3 लाख

13 साल में पर्यटकों की संख्या 19.4 लाख से बढ़कर 77.3 लाख पहुंची, यानी 57.9 लाख की बढ़ोतरी और लगभग 298% ग्रोथ दर्ज हुई।

सांस्कृतिक विरासत-स्थानीय कला को बढ़ावा

पर्यटन का यह नया मॉडल सिर्फ स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र की स्थानीय कलात्मकता को भी वैश्विक बाजार दे रहा है। भोपाल और सीहोर की प्रसिद्ध जरी-जरदोजी कढ़ाई व जूट क्राफ्ट और नर्मदापुरम की नक्काशीदार लकड़ी की कला को मुख्य पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही, सांची का बौद्ध महोत्सव और नागलवाड़ी महोत्सव इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने-बाने को और मजबूत करते हैं।

एक्सप्लेनर

आपकी जिंदगी, जमीन और रोजगार में क्या-क्या बदलाव लाएगा बीएमआर

बीएमआर का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आम लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या गांवों की जमीन छिन जाएगी? क्या रियल एस्टेट में उछाल आएगा? पढ़िए आपके हर सवाल का सीधा जवाब:

Q क्या महानगर बनने से मेरे गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या खेती की जमीन कंक्रीट में बदल जाएगी?

बिल्कुल नहीं। बीएमआर का सबसे बड़ा नियम 'अर्बन-रूरल सिनर्जी' है। गांवों की कृषि भूमि को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि गांवों को पक्की सड़कों, कोल्ड स्टोरेज और शहर की बड़ी मंडियों से जोड़ा जाएगा। आपके उत्पाद शहर में महंगे बिकेंगे और गांव में शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

Q युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए इसमें क्या है?

3,700 एकड़ में बनने वाली 'नॉलेज और AI सिटी' गेम चेंजर है। अब युवाओं को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च की नौकरी के लिए बेंगलुरु या पुणे नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया भर की टेक कंपनियां अपना बेस इसी रीजन में बनाएंगी।

Q रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या असर होगा?

अनियोजित कॉलोनियों पर लगाम लगेगी। 12 हजार वर्ग किमी क्षेत्र के लिए एक ही अथॉरिटी होने से सड़कों, वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी आदि का प्लान पहले से तय होगा। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में 'सेफ और सस्टेनेबल' उछाल आएगा। विदेशी निवेश आने से जमीनों के रेट लॉजिकल और लाभकारी होंगे।

Q आम शहरी को ट्रैफिक और भीड़ से कैसे निजात मिलेगी?

डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए। अब हर दफ्तर, अस्पताल या कॉलेज सिर्फ भोपाल शहर के बीचों-बीच नहीं बनेगा। इन्हें सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, जिससे शहर के बीच का ट्रैफिक दबाव अपने आप कम हो जाएगा।

Q शहरों के अनियंत्रित फैलाव को कैसे रोकेंगे?

बीएमआर के प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' मॉडल के रूप में सामने आएगा। अब तक हाईवे बनने के बाद उसके आसपास अनियोजित कॉलोनियां और बाजार विकसित हो जाते थे, जिससे शहरों का अनियंत्रित फैलाव बढ़ता था। लेकिन नई रणनीति में रेलवे स्टेशन, हाईवे जंक्शन और बड़े ट्रांजिट कॉरिडोर को इकोनॉमिक एंकर बनाया जाएगा। यानी भविष्य के नए आवासीय क्षेत्र, उद्योग और वेयरहाउस उन्हीं इलाकों में विकसित होंगे जहां पहले से मजबूत कनेक्टिविटी मौजूद है।

विशेषताएं... जो इसे बनाती हैं अलग

रीजन की 62 लाख की आबादी बनेगी इकॉनामी का नया पावर हाउस

भोपाल। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी बीएमआर सिर्फ नक्शे पर खिंची लकीर नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 'डेमोग्राफिक पावरहाउस' बनने जा रहा है। लगभग 2.6% की सालाना जनसंख्या वृद्धि दर के साथ यह क्षेत्र 1.7% के राष्ट्रीय औसत को काफी पीछे छोड़ चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2025-26 तक अनुमानित 62 लाख की आबादी के साथ यहां एक विशाल और कुशल कार्यबल होगा, जो मध्य प्रदेश के 2.1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का मुख्य आधार बनेगा।

सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट: बीएमआर के इस 12,099 वर्ग किलोमीटर के बड़े दायरे की 58% आबादी पहले से ही पूरी तरह शहरीकृत हो चुकी है। इसमें अकेले भोपाल जिला 49% आबादी के साथ मुख्य भूमिका निभा रहा है। इतनी बड़ी शहरी आबादी के चलते यहां बड़े पैमाने पर औद्योगिक, रियल एस्टेट और कमर्शियल निवेश के लिए एक विशाल कंज्यूमर मार्केट उपलब्ध है।

मजबूत कार्यबल

वर्ष 2025-26 तक अनुमानित 22 लाख की कामकाजी आबादी के कुशल कार्यबल यहां की सबसे बड़ी ताकत है। मंडीदीप जैसे औद्योगिक केंद्र में असाधारण रूप से 98% और ब्यावरा में 95% लोग खेती की बजाय सीधे हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियों और आधुनिक सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं।

मजबूत ग्रामीण भागीदारी

कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स इस रीजन की आर्थिक रीढ़ हैं। शहरी क्षेत्रों में कार्यबल भागीदारी दर 33% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 42% है। ग्रामीण अंचल की मजबूत भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि विकास की दौड़ में खेत-खलिहान पीछे न छूटें।

मल्टी-पोलर मॉडल : आमतौर पर विकास केवल मुख्य राजधानी के इर्द-गिर्द सिमट जाता है, जिससे शहर चोक होने लगते हैं। लेकिन बीएमआर को मल्टी-पोलर मॉडल पर डिजाइन किया गया है। इसके तहत 2,510 गांवों और शहरी क्षेत्रों में ग्रोथ नोड्स एक्टिव किए जा रहे हैं। ये कस्बे पारंपरिक परिवेश से बाहर निकलकर हाई-टेक केंद्रों में बदलेंगे।

दिल्ली-एनसीआर से लेकर लंदन-शंघाई से मिली प्रेरणा

मेट्रोपॉलिटन रीजन का ग्लोबल विजन बनेगा अब बीएमआर का आधार

एक्सपर्ट व्यू

प्रो. सस्वत बंद्योपाध्याय

दुनिया के सबसे सफल महानगर केवल एक शहर के विस्तार से नहीं, बल्कि कई छोटे शहरों के जुड़ने और सुनियोजित रीजनल प्लानिंग से बने हैं। इसलिए नीति आयोग ने भी सभी राज्यों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के सुझाव भेजे थे।यह खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। उज्जैन-इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्लान इसी सुनियोजित प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है। इससे रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार का भी सिटीज ग्रोथ पर फोकस है। इसलिए अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से केंद्रीय फंड में ज्यादा महत्व मिलेगा। इससे पहले भी दिल्ली-एनसीआर समेत भारत के कुछ राज्यों ने मेट्रोपॉलिटन रीजन के मॉडल को अपनाकर अपने विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारे पास विदेशों का भी अनुभव है। खासकर जर्मनी का फ्रेंकफर्ट रीजन। अब मध्यप्रदेश भी उसी ओर कदम बढ़ा रहा है।

भोपाल के निकट भौंरी में धरातल पर उतरेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन

3700 एकड़ में आकार लेगी नॉलेज और AI सिटी बेंगलुरु-पुणे की तर्ज पर पैदा होंगे लाखों रोज़गार

भोपाल

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन विकास के विस्तार के साथ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 'रिवर्स माइग्रेशन' (घर वापसी) के सबसे बड़े अभियान भी बनने जा रहा है। अब प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च क्षेत्र में नौकरी के लिए बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद की तरफ दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मास्टर प्लान के तहत भोपाल के भौंरी क्षेत्र में 3,700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में प्रदेश की पहली 'नॉलेज और एआई सिटी' विकसित की जा रही है। यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' विजन को जमीन पर उतारेगा। यह आधुनिक हाईटेक और साइबर सिटी की तर्ज पर विकसित की जाएगी, जिसमें विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान केंद्र और स्टार्टअप्स एक ही जगह स्थापित होंगे।

क्या होगा 'नॉलेज और AI सिटी' में खास?

ग्लोबल टेक हब: दिग्गज आईटी व टेक कंपनियां अपना डाटा सेंटर और रिसर्च हब यहां बना सकेंगी।

प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर: फैक्ट्री या दफ्तर बनाने जमीन लेकर सालों इंतजार नहीं। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यानी आते ही काम शुरू।

टर्शियरी सेक्टर को बूम: बीएमआर में सर्विस व आईटी सेक्टर (टर्शियरी सेक्टर) को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। यह सिटी इस सेक्टर का सबसे बड़ा पावरहाउस बनेगी, जिससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार पैदा होंगे। अगले 10 साल में यह आय दोगुना कर देगी।

कनेक्टिविटी की नई परिभाषा... 100 किमी तक की दूरी अब केवल 60 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य

किमी नहीं... मिनटों में नापी जाएगी बीएमआर में दूरी

भोपाल

भोपाल अब केवल राजधानी नहीं रहेगा, बल्कि मध्यप्रदेश की नई आर्थिक धुरी बनने की तैयारी में है। बीएमआर के जरिए सरकार 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 22 शहरों और करीब 2,510 गांवों को ऐसी एकीकृत आर्थिक इकाई में बदलना चाहती है, जहां किसी भी शहर तक अधिकतम 60 मिनट में पहुंचा जा सके। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, शहरी विकास मॉडल और औद्योगिक ढांचे को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। अभी भोपाल से मंडीदीप, सीहोर, विदिशा और रायसेन जैसे शहरों तक पहुंचने में 40 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लग जाते हैं। बीएमआर का सबसे बड़ा लक्ष्य इसे घटाकर अधिकतम 60 मिनट तक सीमित करना है।

प्रदेश और देश से दोगुना सड़क घनत्व, 623 किमी एनएच व 423 किमी स्टेट हाईवे देगा विकास को रफ्तार

उद्देश्य...क्षमता का पूरा उपयोग

शहरों के बीच की दूरी समय के हिसाब से घटेगी, तब निवेश, उद्योग, रोजगार और आवास का दबाव भी संतुलित तरीके से बंटेगा। लॉजिस्टिक हब का विस्तार ताकि मंडीदीप इनलैंड कंटेनर डिपो जैसे औद्योगिक केंद्रों की क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।

50 किमी का आंतरिक घेरा

- सीहोर, विदिशा, रायसेन और मंडीदीप शामिल।
- **उद्देश्य:** शहरों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करना।
- **कनेक्टिविटी:** भोपाल तक 60 मिनट में पहुँचने का लक्ष्य।
- **विजन:** रेसिडेंशियल और कमर्शियल विस्तार को बढ़ावा।

100 किमी का बाहरी घेरा

- शुजालपुर, ब्यावरा, पचोर, नर्मदापुरम, इटारसी सहित 2510 गांव शामिल।
- **उद्देश्य:** भोपाल को लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल हब बनाना।
- **कनेक्टिविटी:** फ्रेट रूट-अल्टरनेट कॉरिडोर से तेज माल ढुलाई।
- **विजन:** नॉलेज सिटी, एआई सिटी और बड़े वेयरहाउस विकसित होंगे।

फायदा रोज़गार, बेहतर आवास और तेज आवागमन की सुविधा। इटारसी कनेक्शन से उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच।

D-11061/26

न्यूज विंडो

युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पड़ताल जारी

तेंदूखेड़ा/तारादेही। थाना तारादेही क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारसबगली में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान कीर्ति पाल पिता दशरथ पाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम सारसबगली के रूप में हुई है। बताया गया कि कीर्ति के माता-पिता रोजी-रोटी के लिए पुणे में मजदूरी करने गए हुए हैं। घटना के समय कीर्ति घर में अकेली थी।

परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर तारादेही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसे साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां पर शव को फ्रीजर में रखवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

नरसिंहपुर। विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल, नरसिंहपुर नगर द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत सुभाष वार्ड स्थित रेस्ट हाउस परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. बृजेश पटेल, डॉ. अमित सोनी, प्रशांत सोनी, इमाम मंसूरी एवं उनकी टीम ने बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार प्रदान किया। शिविर में स्थानीय नागरिकों के रक्तचाप (बीपी) एवं रक्त शर्करा (शुगर) की निःशुल्क जांच की गई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर स्वामी श्री अमृतानंद महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल द्वारा नगर में जनसेवा का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि संगठन समय-समय पर धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को संगठित करने का कार्य भी करता है।

समय पर एंबुलेंस ना पहुंचने से जैतपुर में प्रसूता की मौत चिंताजनक: हिमाद्री

अनूपपुर/ शहडोल। जिला अन्तर्गत जैतपुर मे समय पर एंबुलेंस ना पहुंचने पर प्रसूता की मौत की घटना को सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह अत्यंत चिंताजनक बतलाते हुए कलेक्टर डा केदार सिंह से बात करके नाराजगी जताई है। सांसद हिमाद्री सिंह ने जैतपुर में प्रसूता की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने समय पर उपचार उपलब्ध करवाने और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर डा सिंह से बात करते हुए कहा कि यह हम सबके लिये शर्मनाक है कि समय पर एंबुलेंस ना पहुंचने से प्रसूता की दुखद मौत हो गई। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि एंबुलेंस नहीं है तो हमे बतलाईये ,हम उसकी व्यवस्था करेंगे। सांसद ने जिला सहित सभी अस्पतालों को आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस के प्रस्ताव भी मांगे है ताकि सभी जगह एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा सके।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन

औबेदुल्लागंज। जिले में खाद्य पदार्थों में हो रही निरंतर मिलावट और उससे आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला रायसेन ने सख्त रुख अपनाया है। पंचायत के पदाधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर चंद्रशेखर श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपकर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे। मुख्यमंत्री मिलावट से मुक्ति अभियान के अनुरूप जिले में भी प्रभावी और निरंतर कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। ग्राहक पंचायत ने मांग की है कि दूध, मावा, घी, तेल, मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों की नियमित और सघन जांच सुनिश्चित की जाए। विशेषकर त्योहारों और विवाह सीजन के दौरान विशेष जांच अभियान चलाने तथा बाजारों से नियमित नमूने लेकर उनकी समयबद्ध जांच कराने पर जोर दिया गया। ग्राहक पंचायत ने दोषी व्यापारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, आमजन की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने और जन-जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है, ताकि मिलावटखोरों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

पांदुर्ना में भाजपा पार्षद के कार्यालय में चोरों ने लगाई सेंध, शिकायत पर पड़ताल जारी

पांदुर्णा। शहर में देर रात पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने स्थित भाजपा पार्षद प्रदीप कामदार के कार्यालय नमामि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में अज्ञात चोरों ने धावा बोल सेंध लगा दी। बदमाश शटर और कांच तोड़कर अंदर घुसे तथा काउंटर में रखे करीब 5 हजार रुपए नकद चुराकर फरार हो गए।गुरुवार सुबह कार्यालय खुलने पर चोरी का पता चला। कर्मचारियों ने शटर टूटा और कांच बिखरा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।

जुमे की नमाज के लिए अतिरिक्त पुलिसबल तैनात

परिसर से सटे खुले स्थान पर दोपहर में होगी नमाज

धार। दोपहर मेट्रो

जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट हैं, एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में शहर में अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। नगर के प्रमुख मार्गों पर सुबह से ही पुलिस रहेगी। भोजशाला के पहुंचकर मार्ग पर लगातार पुलिसबल भ्रमण करेगी। भोजशाला के 100 मीटर दायरे पर थ्री लेयर सुरक्षा रहेगी। टीआई, डीएसपी व एसडीओपी सहित करीब 350 का पुलिसबल सुरक्षा के चलते मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करवाने की सबसे बडी जिम्मेजदारी जिला प्रशासन की है। प्रशासन को सबसे पहले जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्थान तय करना होगा, जो न्यायालय की भावना और सुरक्षा मानकों के अनुरुप हो। इसके साथ ही पूजा और नमाज के लिए आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकासी मार्ग तय करना, सुरक्षा घेरा बनाना, भीड नियंत्रण करने जैसे महत्वपूर्ण तैयारी करनी होगी। कल 17 जुलाई को प्रशासन की परीक्षा का दिन होगा। इधर बारिश का मौसम होने से नमाज को किसी खुले स्थान पर करवाने में दिक्कत आएगी। ऐसे में नमाजियों के लिए अस्थाहई टैंट की व्यवस्था करनी होगी।

दरअसल साल के पहले माह जनवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। 22 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के अवसर पर प्रशासन ने दोनों समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हुए अलग-अलग व्यवस्था की थी। उस दिन हिंदू समाज ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में अखंड पूजा-अर्चना की थी, जबकि मुस्लिम समाज के लिए बाहरी क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान पर नमाज की प्रशासन व्यवस्था की गई थी। दोनों समुदायों के आने-जाने के रास्ते भी अलग रखे गए थे। प्रशासन उस समय पूरे. आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सफल रहा था। शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, ऐसे में इस मर्तबा उसी मॉडल को आधार बनाया जा सकता है।

भोज उत्सव समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। हिंदू समाज को भोजशाला परिसर में पूजा का अधिकार यथावत मिला है। नमाज को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। भोजशाला के 100 मीटर संरक्षित और 300 मीटर आरक्षित क्षेत्र से बाहर कहीं भी नमाज हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अलग से व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मे दारी हैं, हमारी पूजा मंदिर में ही होगी। नमाज इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार पठान ने बताया कि कमाल मौला मस्जिद में मुस्लिम समाज कई वर्षों से जुमे से की नमाज अदा करता आया है। कुछ दिन पूर्व व्यवस्था बंद हो गई थी, जिसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश दिया है। यह अंतिम फैसला नहीं है, अब प्रशासन को नमाज पढवाने की उचित व्यवस्था करना है।

रहवासी क्षेत्र में घूम रहे रेडियो कॉलर वाले नर बाघ का रेस्क्यू, वन विहार भेजा जाएगा

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) की टीम ने लंबे समय से रहवासी क्षेत्रों के आसपास विचरण कर रहे रेडियो कॉलर युक्त लगभग तीन वर्षीय नर बाघ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे भोपाल के वन विहार भेज दिया है। वन विभाग के अनुसार बाघ के लगातार आबादी वाले क्षेत्रों के समीप रहने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका बनी हुई थी। एसडीओ आशीष खोबरागडे ने बताया कि उक्त बाघ पिछले छह माह से नर्मदापुरम वनमंडल के रहवासी क्षेत्रों के आसपास सक्रिय था। इससे पहले भी 1 अप्रैल 2026 को उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया था, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से आबादी वाले इलाकों की ओर लौट आया। स्थिति को देखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), मध्यप्रदेश से अनुमति प्राप्त कर दोबारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वन विभाग ने बताया कि यह अभियान लगातार निगरानी, तकनीकी ट्रैकिंग, पांच प्रशिक्षित हाथियों और मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों से सफल बनाया गया। अभियान में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदापुरम वनमंडल की टीम ने संयुक्त रूप से काम किया।

जागरूकता रैली निकालकर दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

सागर। दोपहर मेट्रो

नशा मुक्ति अभियान 2.0 का शुभारंभ सागर में उत्साह एवं जनसहभागिता के साथ किया गया। अभियान का उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा जनसहयोग के माध्यम से स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज का निर्माण करना है। जिला मुख्यालय स्तर पर अभियान का शुभारंभ खेल परिसर से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नशा मुक्ति शपथ के साथ हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, खिलाड़ियों एवं नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, न ही अपने परिवार अथवा परिचितों को नशे के लिए प्रेरित होने देंगे तथा नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे। खेल परिसर से एक विशाल जन-जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली खेल परिसर से प्रारंभ होकर पीली कोठी, कालीचरण चौराहा, सिविल लाइन सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः खेल परिसर पहुंची। रैली में शामिल प्रतिभागियों ने हाथों में नशा मुक्ति संबंधी संदेशों वाली तख्तियां एवं बैनर लेकर आमजन को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। मार्ग में नागरिकों द्वारा रैली का स्वागत करते हुए अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रखकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास एवं सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के साथ-साथ सागर जिले के सभी 35 थाना क्षेत्रों में भी ÷नशा मुक्ति अभियान 2.0 के अंतर्गत जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

नशा मुक्ति अभियान को भी हरी झंडी

डिंडोरी में 5 संदीपनी विद्यालयों का एक साथ हुआ लोकार्पण

डिंडोरी। दोपहर मेट्रो

डिंडोरी में पांच संदीपनी विद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया गया। नरिया संदीपनी विद्यालय से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते और भाजपा जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। इन विद्यालयों का निर्माण लगभग 16 करोड़ 16 लाख 171 रुपये से हुआ है। लोकार्पण समारोह से पहले परिसर में वृक्षारोपण किया। पुलिस विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और हितलाभ का वितरण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन भी चखा।

कलेक्टर ने चलाई धान रोपाई मशीन

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

कृषक कल्याण वर्ष के तहत जिले में कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि प्रक्षेप पवारखेड़ा में पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने स्वयं मशीन चलाकर किया। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर किसानों को इनका लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि कृषि में आधुनिक मशीनों के उपयोग से किसानों की लागत कम होगी, श्रम की बचत होगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उपसंचालक कृषि रविकांत सिंह ने बताया कि पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन एक दिन में 8 से 10 एकड़ क्षेत्र में धान की रोपाई कर सकती है, जबकि इतना कार्य करने के लिए सामान्यतः करीब 100 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इससे समय और श्रम दोनों की उल्लेखनीय बचत होती है। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवेंद्र प्रताप सिंह, उपसंचालक कृषि रविकांत सिंह, कृषि प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य यू.के. शुक्ला, कृषि यंत्री इंदर सिंह धाकड़, भाजपा किसान मोर्चा एवं कुबोटा कंपनी के प्रतिनिधि साजिद सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

छात्र समागम में 430 विद्यार्थियों का किया सम्मान

मंडीदीप। दोपहर मेट्रो

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भोजपुर जिले की मंडीदीप इकाई द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छात्र समागम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडीदीप नगर के विभिन्न विद्यालयों के 430 मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले, प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले, खेल, सामाजिक एवं विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र पटवा रहे, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र मालवीय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर। परिषद के इकाई अध्यक्ष ने परिषद की भूमिका रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उद्देश्यों, छात्र हित में किए जा रहे कार्यों तथा राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र पटवा ने सम्मानित विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच ही सफलता का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि महेंद्र मालवीय ने परिषद के स्थापना वर्ष 1949 से लेकर आज तक के गौरवशाली इतिहास, छात्र आंदोलनों, सेवा, संगठन एवं राष्ट्र निर्माण में परिषद की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से परिषद की रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर समाज एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में नगर मंत्री ने सभी अतिथियों, सम्मानित विद्यार्थियों, अभिभावकों, विद्यालय परिवार एवं उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।

मेट्रो एंकर | समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य होगा नागद्वारी मेला

30 जुलाई तक पूरी हों तैयारियां: कलेक्टर

नर्मदापुरम/पचमढ़ी। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध नागद्वारी मेला इस वर्ष 8 से 17 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीते दिन को पचमढ़ी में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी विभागों को 30 जुलाई तक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस. थोटा, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एसडीएम आकिब खान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के उपसंचालक ऋषभा नेताम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने एसडीएम पिपरिया को मेले के लिए अलग कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। प्रमुख स्थानों पर वाहन किराया सूची और कंट्रोल रूम के फोन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता मिल सके। लोक निर्माण विभाग को नागद्वारी ट्रेक मार्ग, पुल, सीढ़ियां, रेलिंग और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं एमपीआरडीसी को भूस्खलन या सड़क बाधित होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए अमला और क्रेन तैनात रखने को कहा गया।

मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। पर्याप्त एंबुलेंस, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, स्नेक बाइट के लिए एंटी-वेनम किट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वच्छ पेयजल और खाद्य गुणवत्ता पर निगरानी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति, नियमित क्लोरीनेशन और पानी की जांच करने के निर्देश दिए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच कर फूड प्वाइजनिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा गया।

सफाई, बिजली और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था

नपा और साडा को पूरे मेला क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाने, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने और पर्याप्त डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही मोबाइल टॉयलेट, निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षित विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने को कहा गया।

मंडला में नर्मदा नदी में बुजुर्ग डूबा, तलाश जारी

मंडला। दोपहर मेट्रो

मंडला बाईपास स्थित नर्मदा पुल के नीचे पीपरपानी गांव के पास नर्मदा नदी में नहाते समय एक बुजुर्ग डूबकर लापता हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर देर शाम तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन बुजुर्ग का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा दो दशक पुराना प्रतिबंधित दवा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में

इंग्स को हकीम की दवा बता सच छिपाते रहे शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ

पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी के दावे से फिर चर्चा में आया 2006 का विवाद

जांच रिपोर्ट और प्रतिबंध ने खड़े किए कई सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा करीब दो दशक पुराना प्रतिबंधित दवा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव आरवीएस मणि के एक हालिया बयान ने उस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का नाम सामने आया था। मणि ने दावा किया कि जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, तब कुछ खिलाड़ी प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर पहुंचे थे और इस बात को उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने स्वीकार भी किया था। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया।

अक्टूबर 2006 में भारत में प्रतिष्ठित एकदिवसीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। पाकिस्तान का पहला मुकाबला श्रीलंका से होना था, लेकिन मैच से ठीक पहले टीम के दो प्रमुख तेज गेंदबाजों के प्रतिबंधित दवा जांच में असफल पाए जाने की खबर ने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तत्काल दोनों खिलाड़ियों को निलंबित करते हुए स्वदेश लौटने का आदेश दे दिया। बोर्ड ने उस समय बताया था कि खिलाड़ियों के नमूनों की जांच विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराई गई थी, जहां दोनों के नमूनों में प्रतिबंधित पदार्थ की पुष्टि हुई।

बेगुनाही का दावा, लेकिन नहीं मिला कोई प्रमाण

शोएब अख्तर ने शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई प्रतिबंधित दवा जानबूझकर नहीं ली और वे केवल एक हकीम द्वारा दी गई दवा का सेवन कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से क्रिकेट खेला है और अपनी गति बढ़ाने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं थी। लेकिन जांच के दौरान वे अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सके। न तो हकीम की दवा से जुड़ा विश्वसनीय रिकॉर्ड सामने आया और न ही यह साबित हो पाया कि उनके शरीर में मिला प्रतिबंधित पदार्थ किसी वैध उपचार का हिस्सा था।

दोबारा जांच का मौका भी ठुकराया

जांच समिति ने दोनों खिलाड़ियों को दोबारा जांच कराने का अवसर भी दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तीन सदस्यीय अनुशासन समिति ने सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। शोएब अख्तर पर दो वर्ष और मोहम्मद आसिफ पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। जांच समिति ने स्पष्ट कहा था कि दोनों खिलाड़ियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन वे अपनी बेगुनाही साबित करने में असफल रहे। जांच प्रक्रिया, नमूनों की सुरक्षा और प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली।

पूर्व अधिकारी के दावे से फिर उठे सवाल

आरवीएस मणि ने अपने बयान में यह भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में प्रतिबंधित मादक पदार्थों का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। उन्होंने दावा किया कि टीम के तत्कालीन विदेशी प्रशिक्षक बॉब वूल्मर भी इस प्रवृत्ति के खिलाफ थे। मणि के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के कुछ महीनों बाद वूल्मर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिससे उस दौर के कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। हालांकि, वूल्मर की मृत्यु के संबंध में विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच में हत्या के दावे सिद्ध नहीं हो सके थे और मामले को लेकर अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए थे। लेकिन शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का प्रतिबंधित दवा मामला आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे विवादित अध्यायों में गिना जाता है, जिसने खिलाड़ियों की बेगुनाही के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

दूसरे वनडे में सीरीज जीतने उतरेगा भारत

गिल की फिटनेस और रोहित के बल्ले पर नजर

कार्डिफे, दोपहर मेट्रो

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम आज दूसरे मुकाबले में सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टी20 सीरीज में मिली निराशाजनक हार के बाद वनडे प्रारूप में भारत ने दमदार वापसी की है और अब उसकी नजरें कार्डिफ के सोफिया गार्डेंस में जीत के साथ अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। हालांकि मैच से पहले कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है।

गिल की चोट ने बढ़ाई चिंता

पहले वनडे में 80 रन की शानदार पारी खेलने वाले शुभमन गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब तक उनकी फिटनेस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि गिल दूसरे वनडे तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला मैच से पहले लिया जाएगा। यदि गिल नहीं खेलते हैं तो भारत को शीर्ष क्रम में बदलाव करना पड़ सकता है।

रोहित शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पहले वनडे में बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव जरूर किया है, लेकिन लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन की जरूरत अब पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है। पिछले साल अक्टूबर से अब तक खेले गए 13 वनडे में रोहित ने एक शतक और चार अर्धशतकों की मदद से 563 रन बनाए हैं, लेकिन टीम में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच उनसे हर मैच में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

बुमराह की वापसी ने बढ़ाया भरोसा

भारत के लिए सबसे सकारात्मक पहलू जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी रही है। 2023 विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलने उतरे बुमराह ने अपनी पुरानी लय की झलक दिखाई। वहीं, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी योगदान देकर टीम संतुलन को मजबूत किया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से टीम प्रबंधन काफी संतुष्ट नजर आया। कार्डिफ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में भारत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गुरनूर बरार की जगह मौका दे सकता है। पहले मैच में बरार ने दो विकेट जरूर लिए थे, लेकिन नौ ओवर में 61 रन खर्च किए थे। यदि यह बदलाव होता है तो कुलदीप यादव को एक बार फिर इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए दोनों के टीम में बने रहने की पूरी संभावना है।

पहलवान अमन सहरावत का शानदार प्रदर्शन सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में जीता स्वर्ण पदक

बुडापेस्ट , एजेंसी

भारत के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने पोल्याक इमरे, वर्गा यानोस और कोज्मा इस्तवान स्मृति सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वैश्विक सर्किट पर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सहरावत ने खिताबी मुकाबले में जॉर्जिया के रोबेर्टी डिंगाशविली को तकनीकी दक्षता के आधार पर 13-3 से करारी शिकस्त दी।

दीपक को मिला कांस्य पदक

भारतीय दल के पदकों की संख्या तब और बढ़ गई जब दीपक ने 61 किग्रा फ्रीस्टाइल में कड़े मुकाबले के बाद कांस्य पदक जीता। दीपक ने प्लेऑफ में अजरबैजान के नुरद्दीन नोवरुजोव को 9-8 से हराया। भारत 65 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में दो और पदक जीतने की दौड़ में बना हुआ है। कुमार मोहित का सामना कांस्य पदक के मैच में कजाखस्तान के नाचिन कुलर से होगा जबकि उनके साथी विशाल कालीरमन तीसरे स्थान के लिए होने वाले अपने प्लेऑफ मुकाबले में कजाखस्तान के ही ओसुमजान दास्तानबेक से भिड़ेंगे।

फीफा वर्ल्ड कप: सात मिनट के अंदर अर्जेंटीना ने पलटा खेल

इंग्लैंड को रौंदकर कटाया फाइनल का टिकट

जॉर्जिया , एजेंसी

अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना का सामना अब खिताबी मुकाबले में स्पेन से होगा। अर्जेंटीना खिताब का बचाव करने से अब महज एक कदम दूर रह गई है। वहीं, इंग्लैंड का सफर सेमीफाइनल में ही थम गया है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में गॉर्डन के गोल की मदद से बढ़त ली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने सात मिनट के अंदर दो गोल करके मैच का रुख पलट दिया।

अर्जेंटीना के लिए सबसे पहले इंजो फर्नांडिज ने गोल दागा और फिर इंजरी समय में लाउतारो मार्टिनेज ने गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई। अर्जेंटीना ने आखिरी समय तक इस बढ़त को बरकरार रखा। लियोनल मेसी भले ही इस मैच में गोल नहीं कर सके, लेकिन दोनों गोल करने में उन्होंने मदद की। मेसी ने अपने शानदार खेल से बताया कि क्यों वह टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना की जीत के बाद मेसी खुशी से झूम उठे और साथी खिलाड़ियों के साथ डांस करने लगे।

मैच में दिखी तल्खी

इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच शुरुआत से ही मैच में तल्खी देखने को मिली। मैच के शुरुआती मिनटों में ही इंग्लैंड और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बीच तकरार हो गई। गेंद के लेने के प्रयास में अर्जेंटीना के एंजो फर्नेंडेज ने तीसरे मिनट में फाउल किया और इसी दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने-सामने आ गए। हालांकि, रेफरी ने खिलाड़ियों को अलग किया। ऐसा पहले हाफ में कई बार हुआ जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए। इंग्लैंड के एलियोट एंडरसन को येलो कार्ड दिखाया गया। 37वें मिनट में एंडरसन ने मेसी को धक्का दिया जिस कारण रेफरी ने उन्हें येलो कार्ड दिखाया।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

13 देशों की भटकन से बॉलीवुड की बुलंदियों तक... कैटरीना की संघर्ष और सफलता की अनोखी कहानी

मुंबई। ग्लैमर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कैटरीना कैफ का सफर जितना चमकदार दिखाई देता है, उतना ही संघर्षों से भरा भी रहा है। 16 जुलाई 1984 को ब्रिटिश हांगकांग में जन्मीं कैटरीना का बचपन किसी एक शहर या देश में नहीं, बल्कि 13 से अधिक देशों में लगातार स्थान बदलते हुए बीता। पिता से अलगाव के बाद उनकी मां सुजैन टरकोट ने अकेले ही आठ बच्चों का पालन-पोषण किया। सामाजिक कार्यों से जुड़ी मां के साथ लगातार यात्राओं के कारण कैटरीना की पढ़ाई भी पारंपरिक स्कूल के बजाय घर पर ही हुई।

महज 14 वर्ष की उम्र में हवाई में मॉडलिंग प्रतियोगिता जीतने के बाद कैटरीना ने लंदन में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें फिल्म बूम से बॉलीवुड में मौका दिया, लेकिन फिल्म असफल रही। हिंदी भाषा पर कमजोर पकड़ के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और एक फिल्म से बाहर भी होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हिंदी और उर्दू की विशेष ट्रेनिंग ली, देवनागरी सीखी और अभिनय पर लगातार मेहनत की।

बॉलीवुड में संघर्ष के दौरान कैटरीना ने दक्षिण भारतीय सिनेमा का रुख किया। तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी से उन्हें बड़ी सफलता और अच्छी फीस मिली। इसके बाद मैंने प्यार क्यों किया?, नमस्ते लंदन, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और धूम 3 जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नमस्ते लंदन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और राजनीति में उनके अभिनय को भी खूब सराहा गया।

अभिनय के साथ कारोबार में भी बनाई पहचान

फिल्मी करियर के साथ कैटरीना ने व्यवसाय की दुनिया में भी मजबूत कदम रखा। वर्ष 2019 में उन्होंने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी लॉन्च किया, जिसने कम समय में बड़ी सफलता हासिल की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 में ब्रांड की ग्रॉस सेल्स 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। ब्रांड ने भारतीय बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। व्यावसायिक सफलता के साथ कैटरीना सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। वह अपनी मां द्वारा स्थापित संस्था के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में सहयोग करती हैं।

बच्चों के स्कूल जाने पर भावुक हुईं पंखुड़ी , रोते हुए बोलीं- पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए

टेलीविजन अभिनेत्री पंखुड़ी रोड़े के जुड़वां बच्चे राध्या और रादित्य ने स्कूल की अपनी नई पारी शुरू कर दी है। इस मौके पर अभिनेत्री भावुक नजर आईं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी भावनाएं साझा कीं। पंखुड़ी ने इंस्टाग्राम पर बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ तस्वीरें साझा कीं। पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह आमतौर पर आसानी से नहीं रोतीं, लेकिन पिछले तीन मौकों पर उनकी आंखें नम हो गईं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी।

पंखुड़ी ने उन पलों का जिक्र करते हुए लिखा, पहली बार मेरी आंखों में आंसू तब आए, जब मैं बच्चों के लिए स्कूल देखने के गई थी। वहां की सीढ़ियों और गलियारों को देखकर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी बार पेरेंट्स ओरिएंटेशन में शामिल होने के दौरान मेरे आंसू छलक आए। तीसरी बार, स्कूल के पहले दिन की ठीक एक रात पहले जब मैं बच्चों को सुलाकर कुछ लिखने बैठीं, तो आंखों से आंसू बहने लगे।

उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। उनके मुताबिक, स्कूल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन के अगले कई वर्षों, उनके सपनों, सीख और अनगिनत यादों की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि स्कूल वह जगह है, जहां बच्चे खुद को पहचानते हैं और ऐसे दोस्त बनाते हैं, जो जीवनभर साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आंसू दुख के नहीं, बल्कि बच्चों को आगे बढ़ते देखने की खुशी के थे। पंखुड़ी ने यह भी बताया कि बच्चों के जन्म के समय उनके डॉक्टर ने उनसे पूछा था कि वह बच्चों की चिंता करना कब बंद करेंगी। इसके बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के लिए प्यार और चिंता माता-पिता के साथ जीवनभर रहती है।

मेट्रो बाजार

वाहनों की थोक बिक्री जून में 24.1% बढ़कर 3.88 लाख यूनिट्स के पार

दिल्ली । भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री (कंपनियों द्वारा डीलर्स को बिक्री) जून में सालाना आधार पर 24.1 प्रतिशत बढ़कर 3,88,144 यूनिट्स रही है। इससे पिछले वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 3,12,851 यूनिट्स था। यह जानकारी इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की ओर से बुधवार को जारी डेटा में दी गई। सियाम के डेटा के मुताबिक, यात्री वाहनों में यूटिलिटी व्हीकल (यूवी) सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है और जून में इसकी सालाना वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत रही और वॉल्यूम 2,17,228 यूनिट्स रही।

यात्री गाड़ियों की बिक्री सालाना आधार पर 15.7 प्रतिशत बढ़कर 98,610 यूनिट्स हो गई है। वैन की बिक्री सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत बढ़कर 10,230 यूनिट्स पर पहुंच गई है। दोपहिया वाहन श्रेणी ने भी मजबूत रफ्तार बनाए रखी। जून में कंपनियों की ओर से डीलरों को भेजे गए दोपहिया वाहनों की संख्या 18.6 प्रतिशत बढ़कर 18,51,400 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 15,61,283 यूनिट्स पर था। दोपहिया वाहनों में स्कूटर सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी रही। इसकी घरेलू बिक्री 39.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 7,44,823 यूनिट्स पर पहुंच गई।

वहीं, मोटरसाइकिल की बिक्री 6.4 प्रतिशत बढ़कर 10,56,422 यूनिट्स हो गई, जबकि मोपेड की बिक्री कम आधार के चलते 50.4 प्रतिशत बढ़कर 50,155 यूनिट्स हो गई है। तिपहिया वाहनों की डीलरों को बिक्री सालाना आधार पर 26.1 प्रतिशत बढ़कर 77,951 यूनिट्स हो गई है, जबकि पिछले वर्ष जून में यह आंकड़ा 61,828 यूनिट्स पर था।

ऐतिहासिक: भारत-यूके एफटीए से द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद

नई दिल्ली । भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) बुधवार से लागू हो गया है। इसे आर्थिक नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके तहत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने, औद्योगिक इनोवेशन को तेज करने और पेशेवर स्तर पर आवाजाही को बढ़ाने के लिए एक नियामक ढांचे के तौर पर काम करेगा।

इस एफटीए के साथ ही भारतीय निर्यातकों को यूके का बड़ा बाजार मिल गया है, जिसे दुनिया के सबसे प्रीमियम कंज्यूमर मार्केट्स में गिना जाता है। इस समझौते के चलते भारत के 99 प्रतिशत सामान को यूके में जीरो-ड्यूटी के साथ एंट्री मिलेगी, जिससे असल में देश के यूके के साथ कुल व्यापार मूल्य का लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा ड्यूटी-फ्री हो जाता है। इससे समझौते के फायदे अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एफटीए से पहले भारत से यूके को निर्यात किए जाने वाले प्रोसेस्ड फूड पर 70 प्रतिशत तक ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर शून्य हो गई है। सब्जियों पर ड्यूटी पहले के 20 प्रतिशत तक से घटकर शून्य हो गई है। ट्रांसपोर्ट/ऑटो पर ड्यूटी पहले के 18 प्रतिशत तक से घटकर शून्य और कपड़ा पर ड्यूटी पहले के 12 प्रतिशत तक से घटक शून्य हो गई है। इसके अलावा केमिकल, आभूषण, प्लास्टिक एवं रबर और घड़ियों आदि पर ड्यूटी भी शून्य हो गई है। सामान के अलावा इस एफटीए से पेशेवरों को बड़ी संख्या फायदा होगा। इस एफटीए के तहत यूके ने भारतीय कर्मचारियों के लिए डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (डीसीसी) की छूट को तीन साल से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया है। इससे यूके में अस्थायी रूप से काम करने गए लोगों के लिए डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

कालू वॉटरफॉल में दिखा रिवर्स वॉटरफॉल

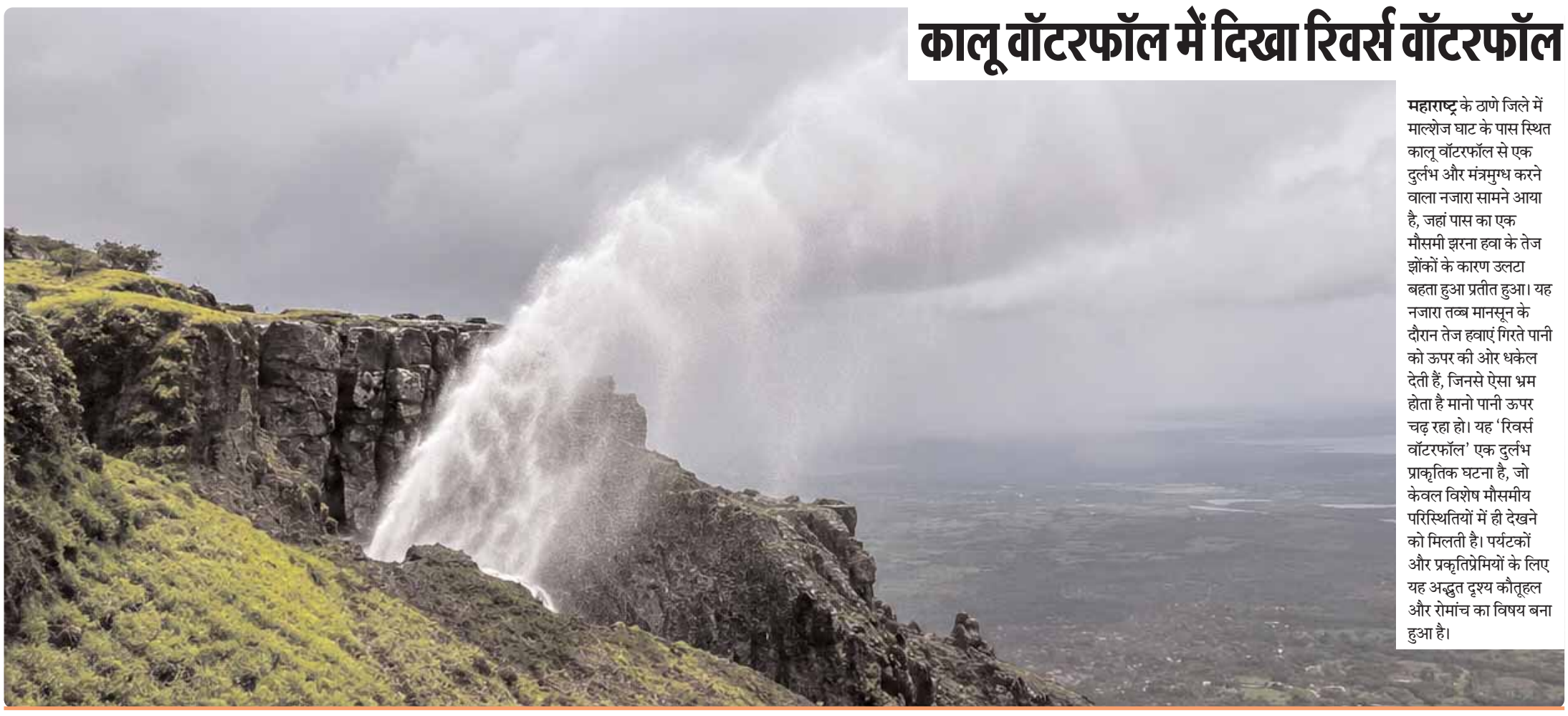

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में माल्शेज घाट के पास स्थित कालू वॉटरफॉल से एक दुर्लभ और मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा सामने आया है, जहां पास का एक मौसमी झरना हवा के तेज झोंकों के कारण उलटा बहता हुआ प्रतीत हुआ। यह नजारा तब्ब मानसून के दौरान तेज हवाएं गिरते पानी को ऊपर की ओर धकेल देती हैं, जिनसे ऐसा भ्रम होता है मानो पानी ऊपर चढ़ रहा हो। यह 'रिवर्स वॉटरफॉल' एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है, जो केवल विशेष मौसमीय परिस्थितियों में ही देखने को मिलती है। पर्यटकों और प्रकृतिप्रेमियों के लिए यह अद्भुत दृश्य कौतूहल और रोमांच का विषय बना हुआ है।

भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक

दावा... हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट और सप्लायर्स की लिस्ट डार्क वेब पर डाली

चेन्नई. एजेंसी

तमिलनाडु स्थित भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों के लीक होने का दावा सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय हैकर समूह 'वर्ल्ड लीक्स' ने कथित तौर पर प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, उपकरणों के मूल्यांकन दस्तावेज और बीमा संबंधी रिकॉर्ड सहित करीब 19 हजार फाइलों की जानकारी सार्वजनिक करने का दावा किया है। रिपोर्टों के अनुसार यह डेटा रिलायंस समूह से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित बताया जा रहा है।

रिलायंस समूह ने स्वीकार किया है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर सेवा प्रदाता के सर्वर पर आंशिक सेंधमारी हुई थी और मामले की जानकारी सरकार को दे दी गई है। हालांकि कंपनी ने चोरी हुए डेटा की प्रकृति का खुलासा नहीं किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दावे सही साबित होते हैं तो यह घटना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी साबित हो सकती है। फिलहाल दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

लीक में क्या-क्या शामिल होने का दावा

हैकर समूह के दावों के अनुसार लीक हुए डेटा में प्लांट के कुछ हिस्सों के नक्शे, सप्लायर नेटवर्क, बैठक और निरीक्षण रिकॉर्ड, उपकरणों की समीक्षा रिपोर्ट तथा बीमा संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। कुल 19 हजार संवेदनशील फाइलों का जिक्र किया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि ये दस्तावेज वर्ष 2016 से 2025 के बीच के हो सकते हैं। हालांकि स्वतंत्र एजेंसियों ने अभी तक इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। यदि इन दावों में सच्चाई पाई जाती है, तो इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और डेटा प्रबंधन प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

कौन है वर्ल्ड लीक्स हैकर ग्रुप

वर्ल्ड लीक्स को कथित तौर पर एक रैनसमवेयर और डेटा उगाही करने वाले साइबर अपराधी समूह के रूप में जाना जाता है। इस तरह के समूह कंपनियों और संस्थानों के सर्वर में सेंध लगाकर संवेदनशील जानकारी चुराते हैं और फिरौती की मांग करते हैं। **भुगतान नहीं होने की स्थिति में डेटा को डार्क वेब या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जारी करने की धमकी दी जाती है।** इस समूह ने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को निशाना बनाया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संगठित साइबर गिरोह दुनिया भर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ता खतरा बनते जा रहे हैं।

कुडनकुलम प्लांट ही क्यों

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है। यह देश के सात प्रमुख परमाणु संयंत्रों में सबसे बड़ा माना जाता है। वर्तमान में यहां कई इकाइयां बिजली उत्पादन कर रही हैं, जबकि यूनिट-3 और यूनिट-4 का निर्माण जारी है। इन दोनों इकाइयों के चालू होने के बाद संयंत्र की उत्पादन क्षमता में लगभग 2000 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। यह परियोजना भारत और रूस के सहयोग से विकसित की जा रही है और दक्षिण भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

...साइबर सुरक्षा पर चिंता

परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बिजली ग्रिड, बंदरगाह और रक्षा प्रतिष्ठान जैसे महत्वपूर्ण ढांचे किसी भी देश की सुरक्षा से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे संस्थानों से तकनीकी दस्तावेज, नक्शे और सप्लाई चेन की जानकारी गलत हाथों में पहुंचने पर सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। अब केवल भौतिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस घटना ने सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के बीच डेटा सुरक्षा, क्लाउड स्टोरेज और थर्ड पार्टी सर्वर प्रबंधन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। आने वाले समय में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है।

इसरो में इस्तीफों का दौर

गगनयान, चंद्रयान-3 से जुड़े 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने छोड़ी नौकरी

बेंगलुरु. एजेंसी

भारत का अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) इस समय बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। इसरो के कई सीनियर साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट इस्तीफा दे रहे हैं और प्राइवेट स्पेस कंपनियों की तरफ जा रहे हैं। एक के बाद एक पिछले एक साल में करीब 100 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दिए हैं। इसरो से वैज्ञानिकों के इस तरह के इस्तीफे को रोकने के लिए भारत सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अंतरिक्ष विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अब ऐसे किसी भी मामले को केंद्र स्तर पर सीधे मंजूरी नहीं मिलेगी, बल्कि अंतिम मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर भेजा जाएगा।

दरअसल, हाल ही में इस्तीफा देने वालों में गगनयान और चंद्रयान-3 जैसी बड़ी परियोजनाओं के कई प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर्स भी शामिल हैं। इसको लेकर सरकार का मानना है कि इस तरह अचानक काम छोड़ने से राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। जिसके चलते सरकार ने वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है। हालांकि, इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इससे परियोजनाओं को अचानक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। वहीं, वैज्ञानिकों के इस्तीफे रोकने के लिए 14 जुलाई को एक नया अंदरूनी फरमान जारी किया है। इंटरनल मेमोरेंडम में कहा गया है कि हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स से जुड़े 'ग्रुप-ए' के साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) या इस्तीफे के अनुरोधों को अब रूटीन के तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि हाल के दिनों में नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों की संख्या में आई तेजी के कारण राष्ट्रीय महत्व की बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर गंभीर असर पड़ा है।

इस लिए छोड़ रहे साइंटिस्ट

बता दें कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अनुभवी वैज्ञानिकों की डिमांड बढ़ गई है। प्राइवेट कंपनियां मुह मांगा पैसा दे रही हैं। यही वजह है कि इसरो के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं।

PoK में प्रदर्शनकारियों ने आखिरी समय में रोका 'लॉन्ग मार्च', 21 तक का अल्टीमेटम

इस्लामाबाद. एजेंसी

पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे नेताओं ने अपना 'लॉन्ग मार्च' रोक दिया है। यह फैसला आंदोलन की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) और पाकिस्तान की सरकार में लंबी बातचीत के बाद किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस्लामाबाद को 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। जॉइंट अवामी ऐक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान उनकी मांगे न पूरी की गईं तो 22 जुलाई से उनका मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि सभी धरने पहले की

तरह जारी रहेंगे और जन-आंदोलन भी चलता रहेगा। वहीं, बुधवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मार्च निकाला। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आई और जेएएसी नेताओं के साथ बातचीत का दौर शुरू किया।

जुड़वां बच्चे होने पर दूसरी बार भी मिलेगी मैटरनिटी लीव: हाई कोर्ट

हैदराबाद। तेलंगाना हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पहली गर्भावस्था में जुड़वां बच्चे होने पर किसी महिला को दूसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुड़वां बच्चों का जन्म एक प्राकृतिक और जैविक घटना है, जिस पर महिला का कोई नियंत्रण नहीं होता। मामला मंचेरियल जिले के सरकारी गर्ल्स कॉलेज की जूनियर इंग्लिश लेक्चरर जाडी स्वरूप रानी से जुड़ा था। वर्ष 2023 में उन्हें जुड़वां बच्चे हुए थे और 2026 में तीसरे बच्चे के जन्म पर उनकी 180 दिन की मैटरनिटी लीव की अर्जी यह कहकर खारिज कर दी गई कि उनके पहले से दो बच्चे हैं।

भूख हड़ताल के 19वें दिन सोनम वांगचुक बोले- आप सब 20 जुलाई को तैयार रहें

नई दिल्ली, एजेंसी

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 19वें दिन भी जारी है। लंबे समय से जारी इस हड़ताल के कारण उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घट गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी शारीरिक स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। वहीं, सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने संसद तक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने के लिए कहा है। वांगचुक ने कहा कि उनसे व्रत तोड़ने के बजाय लोग उनके

आंदोलन का समर्थन करें। वहीं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम का स्वास्थ्य नियमित तौर पर चेक हो रहा है। अदालत ने पूछा कि क्या सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं उनकी तरफ से जब भी हमें अनुमति जाएगी सरकारी डॉक्टर उनकी नियमित जांच करना शुरू कर देंगे। तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि अब सरकारी चिकित्सक उनकी नियमित जांच करेंगे।

मेट्रो एंकर नर्मदा की सुरंग से बदलेगी विंध्य की तकदीर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल करेंगे निरीक्षण

कटनी में देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग बनकर तैयार

कटनी. दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब बनकर तैयार हो गई है। करीब डेढ़ दशक से चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। टनल के ब्रेकथ्रू के साथ पहली बार बिना किसी पंप या लिफ्ट के बरगी बांध का पानी विंध्य की धरती तक पहुंचेगा। यह सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बदलने वाली ऐतिहासिक परियोजना मानी जा रही है।

किसानों के लिए नर्मदा का पानी बनेगा नई उम्मीद

परियोजना पूरी होने के बाद कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से नियमित सिंचाई मिलेगी। वर्षों से मानसून और भूजल पर निर्भर किसानों के लिए यह परियोजना किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। इतना ही नहीं, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा के 1450 गांवों की करीब 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि भी इस योजना से सिंचित होगी। परियोजना के तहत मुख्य सुरंग के अलावा लगभग 12 किलोमीटर लंबी ओपन कैनाल और एक किलोमीटर लंबी कट-एंड-कवर संरचना भी तैयार की गई है।

15 साल का संघर्ष... पहाड़, पानी और तकनीकी चुनौतियों पर मिली जीत

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की इस परियोजना को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली और 2011 में निर्माण शुरू हुआ। करीब 30 मीटर गहराई में जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से 11.952 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ऊंचा भूजल स्तर, अचानक बनने वाले सिंकहोल, कोरोना काल की बाधाएं और रास्ते में आई 56 बेहद कठोर चट्टानों ने निर्माण कार्य को कई बार रोक दिया। कई मौकों पर मशीन के कटर और अन्य पुर्जे बदलने पड़े। सुरक्षा के मद्देनजर सुरंग के ऊपर लगभग 20 मीटर चौड़ी भूमि का अस्थायी अधिग्रहण भी किया गया। इस कार्य में लगातार बढ़ती चुनौतियों के कारण परियोजना की लागत 799 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण

नर्मदा टनल का ब्रेकथ्रू होते ही इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बनने के लिए 17 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्लीमनाबाद दौरे की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वर्षों तक इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को पूरा करने वाले इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और कर्मचारियों का सम्मान किया जा सकता है। हालांकि, मुख्यमंत्री के दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। आशीष तिवारी (कटनी कलेक्टर) ने बताया नर्मदा टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी डेढ़ माह का समय और लगेगा। चूंकि अभी रेल लाइन और बिजली संबंधित उपकरण को हटाने जैसी चीजें शेष हैं। वहीं, 17 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरा प्रस्तावित है, जो टनल से करीब पांच किलोमीटर के दूर हेलीपैड से उतरकर पूरे टनल का निरीक्षण करेंगे।

शिमला में रोडवेज बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, कई घायल

शिमला. एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर उपमंडल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस गरटोला के नजदीक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 22 यात्री सवार थे। हादसे में बस के परिचालक जय प्रकाश नेगी तथा डाकू राम, निवासी गांव शाहदू, तहसील ननखड़ी की मौके पर ही मौत हो गई।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रसलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564